

this matter. It is a serious matter. It is a matter of defending the Constitution. Therefore, the Government should allow it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: The House is not being extended only for discussing the Preventive Detention Act. There is other business also. We discussed it at a meeting of the Business Advisory Committee yesterday where representatives of all the Parties were there. Perhaps the hon. Member has in view his 'No-Day-Yet-Named Motion.' I do not know, but during the discussion on the Preventive Detention Act the hon. Member will have full opportunity—I think more than necessary—to attack it and certainly the hon. Member will say when the emergency is there we should not have it. All these things will be discussed. It is so allied that it is very difficult to draw a line of demarcation between the two. So, I think so far as this Session is concerned, Government is not in a position to handle the 'No-Day-Yet-Named Motion.'

SHRI BHUPESH GUPTA: Why?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has given the reason. He said that the Government is not in a position to do it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R. M. HAJARNAVIS): Madam, may I have your indulgence to ask the House for their permission? I have agreed to make a statement at 2.30. The statement is ready. I have to receive Lord Denning, who is coming here, together with the Law Minister. We were told that his plane would arrive at 12:45, but it has been delayed till 2:15. May I have your permission and that of the House to make the statement at 4 o'clock instead of at 2.30?

865 RSD.—3.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the House will grant him that indulgence. Now, the House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1962—Continued.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Mr. Kasliwal. Not here. Mr. P. C. Mitra.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Sir, we were promised a statement at 2.30.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): That will be done later.

श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र (बिहार) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो भार्गव साहब का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ लेकिन इसके माने यह नहीं है कि उनका जो बिल है उसका मैं समर्थन करता हूँ; क्योंकि बिल से यह साफ जाहिर होता है कि तीन चुनावों को देखने के बाद उनमें निराशा पैदा हुई है और यह बिल उस निराशा का द्योतक है। कोई भी कानून ऐसा बनाना चाहिये जिसके लिये कि जनमत का समर्थन रहे और जिसे लागू करना भी सम्भव हो। हम लोगों ने यह कानून तो बना दिया कि असेम्बली कांस्टीट्यूटर्स के लिये ६ हजार या ७ हजार रुपया और पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूटर्स के लिये २५ हजार रुपया खर्च हो सकता है और इसमें बहुत किस्म का प्रतिबन्ध दे दिया है कि अगर फलों-फलों किस्म से खर्चा किया जायेगा तो उस पर कार्यवाही हो सकती है और चुनाव भी खारिज हो सकता है, लेकिन इसकी

[श्री प्रमल चन्द्र मिश्र]

देखभाल करने के लिये, इस पर खबरदारी करने के लिये कोई इंतजाम नहीं किया, जिसका फल यह हुआ कि जिसके पास पैसा है, वह जैसा चाहे खर्च कर सकता है। जितना खर्चा करने की इजाजत दी हुई है, उतना खर्चा कोई गरीब किसान या मजदूर नहीं कर सकता है और जैसा कि हमारे अपोजीशन के मेम्बर ने कहा कि किसानों को और मजदूरों को आना चाहिये और वही हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन अभी भी जितना खर्चा करने की इजाजत है उतना खर्चा भी करने की वे लियाकत नहीं रखते हैं। तो चूंकि यह बिल जनमत जानने के लिये भेजा जा रहा है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विषय पर जब जनमत आयेगा तब आदमी सोच सकेगा कि इसके पीछे जो बेईमानी होती है उसको कैसे बन्द किया जाये। हो सकता है कि चुनाव के तरीके को भी कुछ बदलना पड़े जिससे कि इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मेरा अपना अनुभव तो यह है कि यह जो खर्चा करने की प्रवृत्ति है वह भी आहिस्ता आहिस्ता घटती जायेगी। यह कहना कि पैसा खर्च करने से कोई भी जीत सकता है, यह अधिकांश में ठीक नहीं है। चुनाव के परिणामों से यह मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसा खर्च करने से ही कोई जीते। कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत तो पड़ती है लेकिन जो उम्मीदवार ज्यादा पैसे को दिखाता है वह हार जाता है और जो गरीबी ढंग से काम करता है, धूमता है और अपने लिये कोशिश करता है वह जीत जाता है, ऐसा देखने में आता है। मेरा अपना ख्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता कुछ दिन में पैसा खर्च करके जीतने की जो प्रवृत्ति है वह घट जायेगी।

कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जो शासक पार्टी है वह

बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है और इसीलिये यह बिल लाया गया है कि जो अभी लिमिट है, वह लिमिट नहीं रहे, लेकिन यह बात बिल्कुल निराधार है। मैं समझता हूं कि अगर हिसाब किया जाये, हर एक जिले में कितनी सीटें हैं और हर एक उम्मीदवार के लिये जितना खर्चा होता है उस सब को मिला कर कांग्रेस पार्टी का जो खर्चा है उसका हिसाब किया जाये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के खर्च से वह खर्चा कम है। कभी भी कांग्रेस पार्टी का खर्चा उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यह दूसरी बात है कि दो, चार लीडर्स के लिये कुछ ज्यादा खर्चा हो जाये लेकिन साधारण तौर पर उम्मीदवारों के लिये कांग्रेस पार्टी बहुत कम रुपया खर्च करती है। हम कांग्रेस पार्टी में भी देखते हैं कि जहां पर ज्यादा रुपया खर्च किया गया है वहां क्या हुआ है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि रुपये के बल पर वोट दे। जनता यह समझ गई है कि चुनाव में झूठ बोलना कोई पाप नहीं है और वह समझती है कि जो उम्मीदवार अभी इतना पैसा खर्च करते हैं तो फिर वे जरूर आगे जा कर नफा करेंगे, जरूर कमायेंगे और जब जायज तरीके से कमाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिये यह कमाई नाजायज तरीके से ही हो सकती है। जो ५० हजार या लाख रुपया खर्च करता है, उसको जनता समझती है कि वह जाकर के जरूर बेईमानी करेगा, तो उसका चुनाव नहीं करती है और जब वे चुनाव में सफल नहीं हुए तो वे क्या कमाई करेंगे? अब जैसे सदन का इनडाइरेक्ट एलेक्शन है तो इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कोई खर्च नहीं करते हैं लेकिन हम यह जानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जिनके पीछे पार्टी की ताकत नहीं रहती है, वह इसमें बहुत खर्च करते हैं। दो-एक कंस हम जानते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया है जब कि बाकी आदमी कोई खर्चा नहीं करके आए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी पर जो यह इल्जाम लगाया जा रहा है

कि इसीलिये यह बिल लाया गया है कि खर्च की कोई लिमिट नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी जितना चाहे उतना खर्च कर सके, यह बिल्कुल निराधार है ।

असल बात यह है कि किसी को झूठ लिखने के लिये मजबूर न कीजिये । यही सब से मुख्य बात है । कोई कानून ऐसा नहीं बनाइये कि जो ईमानदार आदमी भी है वह अगर सच्चाई से लिखे तो फिर उसको नुबसान हो जाये । जैसे कि पांच वर्कर्स को अगर कोई एक, एक रुपया खाने के लिये दे देता है तो वह कानून के चक्कर में आ जायेगा; क्योंकि सिर्फ एलेक्शन एजेंट को ही खर्चा दे सकते हैं और दूसरे किसी को नहीं दे सकते हैं । अगर किसी वर्कर को खाने का इन्तजाम कर दीजिये तो वह भी कानून में आ जायेगा; क्योंकि वह वर्कर भी वोटर है और इस तरह रुपया देकर वोट मांगने में आ जाता है । आपने ऐसा कानून बनाया है कि ईमानदार आदमी को भी मजबूरन झूठ लिखना पड़ता है, झूठे कागज़ में सही करना पड़ता है । तो इसीलिये यह प्रस्ताव आया है कि बिल का जनमत जानने के लिये प्रचार होने से बहुत से लोगों की बृद्धि लगने में कोई ऐसा रास्ता मालूम पड़गा जिससे कि किसी को झूठ लिखने के लिये मजबूर नहीं होता पड़े ।

पैसा इकट्ठा करने के बारे में भी कुछ बात कही गई । कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़-बड़े आदमियों से पैसा लेती है । यह बात इस माने में सही है कि कांग्रेस पार्टी बड़े आदमियों से और गरीब आदमियों से सभी से पैसा लेती है । जो चन्दा देता है उससे लिया जाता है, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं लिया जाता है । जहां तक लेने की बात है, सब लेते हैं । अब, यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को इसलिये देते हैं कि उसमें उन्हें लाभ है । किसी को उससे फ़ैवर होने की उम्मीद है, किसी को कोई लाभ होने की उम्मीद है, इसलिये कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं । लेकिन ऐसी पार्टी भी है कि

जिसको आदमी धमकी में आकर देते हैं, अपना नुकसान होने के डर की वजह से देते हैं । तो यह धमकी में देना भी खराब है और लालच में देना भी खराब है । अब कोई पार्टी धमकी देकर लेती है कि अगर यह नहीं करोगे तो यह करेंगे, आपके यहां स्ट्राइक करा देंगे, आपका यह लुटवा देंगे । इस डर से भी देता है । इसलिये किसी भी तरह का दबाव यानी, अगर लालच से दबाव है वह भी खराब है, कोई धमकी से दबाव है वह भी खराब है । इसलिये किसी तरीके से दबाव देना, यानी दोनों ही चीजें खराब हैं और दोनों चीजें बन्द हों इसी को देखना चाहिये ।

अभी अनवर साहब ने कहा कि पार्टी के हिसाब से केन्डीडेट खड़ा किया जाये । यह जो सुझाव उन्होंने दिया है, यह तो मेरी समझ में नहीं आता कि कभी संभव है । किसी भी आदमी से यह कहा जाये कि भाई, आपके यहां से किसी आदमी को चुना जायेगा—और जैसा कि कहा गया, हो सकता है, बिहार का आदमी त्रिचनापली से चुना जाये—तो हर आदमी कम से कम यह चाहता है कि हम वोट देंगे उसी को जिसको हम जानेंगे । उनके पास उम्मीदवार पहुंचें, और अगर नहीं जायेगा तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठ कर कैसे उसको वोट दिलवा सकती है ? चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह हम नहीं समझते हैं कि कोई आदमी उम्मीदवार को बिना जाने वोट देगा । यह तो अच्छी तरकीब नहीं है कि इस तरीके से वोटर को अंधेरे में रखना जिसमें वह जान भी नहीं सके कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा । यह तो हम समझते हैं कि ठीक तरीका नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि जो भी पार्टी का आदमी हो, उसे आदमी का चरित्र विचार करने का भी अधिकार वोटर को होना चाहिये । यह सही है कि कोई भी आदमी पार्टी में आ सकता है, पार्टी में हर कोई कांग्रेस का मेम्बर बन सकता है या कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर बन सकता है । लेकिन यह जानने

[श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र]

का भी रास्ता मिलना चाहिये कि उसका चाल-चलन ठीक उसी तरीके का है कि नहीं, वह सही आदमी है कि नहीं। हो सकता है कि कभी गलत आदमी पार्टी में आ जाये। ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी कभी गलत आदमी को खड़ा नहीं करते हैं; गलत आदमी को खड़ा करते हैं तो जनमत उसके खिलाफ होता है, वह हार भी जाता है। इसलिये हम समझते हैं एक यह तरीका कि पार्टी का नाम रहेगा और केन्डीडेट सामने नहीं आएगा, यह तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि शायद ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा—इतनी बड़ी-बड़ी कांस्टीट्यूएन्सी हैं, इस कांस्टीट्यूएन्सी को छोटा करने का कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं, यह सोचना चाहिये, यानी कांस्टीट्यूएन्सी जितनी छोटी होगी उतना करप्शन का रास्ता घट जायेगा। हमें छोटी कांस्टीट्यूएन्सी के बारे में सोचना है। हम लोगों की कांस्टीट्यूएन्सी बहुत बड़ी होती है जिससे यह अनाचार का रास्ता और ज्यादा खुल जाता है, किसी को भी उसकी खबरदारी करने का इन्तजाम करना बहुत मुश्किल होता है और उम्मीदवार की वोटर से जान-पहचान नहीं रहती है, इसलिये उसको जान-पहचान करने के लिये बहुत खर्चा करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि यह जब जनमत के लिये आयेगा तो यह भी सुझाव आयेगा। जब चीन में ८०० मेम्बर हैं पार्लियामेंट में और अभी ४०० या ५०० और बढ़ाने की बात हो रही है तो क्यों नहीं यहां भी बढ़ें? यहां ५०० जब हो सकता है तो ८०० होने से क्या नुकसान हो सकता है? तो इसी तरीके से यहां असेम्बली या काउन्सिल में ...

श्री शीलभद्र याजी : साढ़े सात सौ यहां भी हैं।

श्री प्रतुल चन्द्र मिश्र : ... बढ़ाने की बात हो सकती है। एक बात कही जा

सकती है कि वे बैठेंगे कहां? जब इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग हम बना सकते हैं, तो नयी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बन सकती है; काउन्सिल, असेम्बली की बिल्डिंग भी बन सकती है।

हम समझते हैं कि यह बिल जो प्रस्तावक साहब ने प्रस्तुत किया है, इस पर जनमत लिये जाने के बाद यह सब रास्ता निकलेगा, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती ताराबाई साठे (महाराष्ट्र) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने भार्गव जी ने जो यह बिल पेश किया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। कई सभा सदस्यों ने और भार्गव जी ने भी बताया है कि यह जो खर्च का हिसाब देने की शर्त है यह न रहे। मैं उनसे सहमत नहीं और इसके क्या क्या कारण हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं।

कई सदस्यों ने बताया है कि गरीब आदमी को चुनाव में खड़े होने की स्थिति हो, इसलिये यह कानून और जो शर्त है, यह निकले। इस देश में कई गरीब आदमी हैं और कई कर्तव्यवान भी हैं और अपने-अपने ताल्लुक में और जिले में काम भी करते हैं। फिर जब उनके पास पैसा नहीं है तो ये चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। आज जो कानून है, उस कानून से लोक सभा के लिये २५,००० रुपये तक और असेम्बली के लिये ७,००० रुपये तक खर्च करने के लिये परमिशन मिली है। तो यह भी बहुत ज्यादा खर्चा है, ऐसा मैं सोचती हूं।

दूसरा कारण कई सदस्यों ने यह बताया है कि यह खर्च का जो हिसाब सरकार को रिटर्निंग आफिसर को देना पड़ता है, उसका झूठा और गलत हिसाब कई लोग दे देते हैं। इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैंने भी लोक सभा का एलेक्शन लड़ा है और मैं आपके सामने यह रख सकती हूं कि मैंने एक पैसे का भी ...

झूठा नहीं रखा है। तो ऐसे भी कई प्रामाणिक केस हो सकते हैं और प्रामाणिकता एलेक्शन के खर्च के बारे में ही नहीं होनी चाहिये; बल्कि हर एक क्षण प्रामाणिकता रखनी चाहिये। तो यह जो गलत बात यहां बताई है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और गरीब आदमियों के लिये जो बताया गया है वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब यह कानून और यह शर्त निकल जायेगी तो गरीब आदमी कभी भी चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकेगा; क्योंकि जो श्रीमंत आदमी है वह बहुत सा खर्चा कर सकेगा।

अब मैं दो एक सूचना देना चाहती हूँ। बहुत दिन पहले चुनाव के वक्त कन्वेन्स भेजने की कुछ आदत थी और आज जब हम वोटर्स या मतदारों के यहां जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे लिये वाहन भेज दो, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आजकल कानून से यह बन्द हो गया है। तो इसलिये, क्योंकि यह कानून से बन्द हो गया है, वोटर्स और मतदार यह मांग नहीं कर सकते हैं और इससे बहुत सा खर्चा कम हो गया है; क्योंकि वाहन के बारे में पहले तो बहुत खर्चा करना पड़ता था। यह खाली एसेम्बली के लिये और लोक सभा के लिये नहीं है। आज कल बहुत से चुनाव हो रहे हैं—कारपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी (नगर-पालिका) है, कोऑपरेटिव बैंक है और पंचायत है, हर एक चुनाव में भारी खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिये यह जो कानून है, यह सब पर ही लगाना चाहिये, खाली एसेम्बली के लिये और लोक सभा के लिये नहीं।

चुनाव के समय जो ज्यादा खर्चा होता है, वह आखीर के दिन होता है और आखीर के दिन में बहुत सा मंडप लगाना पड़ता है। जहां पोलिंग बूथ होते हैं उसके चारों तरफ से मंडप लगाना पड़ा है और सुबह ८ बजे से शाम छः सात बजे तक इधर स्वयंसेवक

बैठते हैं और बहुत बड़ा जलसा चलता है। ये सब मंडप कानून से बन्द होने चाहिये क्योंकि सरकारी लोग उधर होते हैं हर एक पोलिंग बूथ में, वे नम्बर दे सकते हैं। तो ये जो पार्टीज के लिये और लोगों की तरफ से जो ये मंडप रखते हैं, यह सब जब कानून से बन्द हो जायेगा, तो यह सब खर्चा कम हो जायेगा।

दूसरी सूचना मैं यह देना चाहती हूँ कि जलूस की भी बंदी की जाय। आजकल ऐसी आदत हो गई है कि जब चुनाव होता है तब और आखर के दो तीन दिन में बड़े जलूस निकलते हैं। एक पार्टी एक जलूस निकालती है तो दूसरी पार्टी उससे बड़ा जलूस निकालती है और उधर भी बहुत सा खर्चा होता है। बड़े बड़े फोटोज लगते हैं, रिकॉरेंसन्स करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लाइट लगाते हैं और इन जलूसों में पांच-पांच, सात-सात हजार रुपया खर्चा होता है। शहर में यह जलूस और बड़ा होता है। तो यह जलूस कानून से बन्द करना चाहिये। इसके साथ, अगर कोई संस्था या ग्रुप यानी गुट किसी डोनेशन की मांग करता है तो वह मांग भी कानून से बंद होनी चाहिये। जो कोई उम्मीदवार डोनेशन देंगे, उनका भी कैंडीडेचर रद्द होना चाहिये। और जो पोलिटिकल पार्टीज होती हैं वे भी बहुत सा खर्चा करती हैं और उसका हिसाब उम्मीदवार के हिसाब में आता नहीं है। इसलिये मैं ऐसी सूचना देना चाहती हूँ कि हर एक पार्टी को भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिये और रजिस्ट्रेशन करके न केवल चुनाव के वर्ष का, बल्कि हर एक वर्ष का उस पार्टी को हिसाब देना चाहिए सरकार के पास। अगर इलेक्शन में जो खर्चा किया जाता है, उसके बारे में कोई पाबन्दी लगा दी जायेगी कि इतना खर्चा किया जाना चाहिये, तो उससे ज्यादा खर्चा कोई भी पार्टी नहीं करेगी। मेरा यह सुझाव है और कितने लोग इससे सहमत होंगे, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ।

एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि यह जो संशोधन है उससे मैं सहमत नहीं हूँ,

[श्री मती नाराबाई साठे]

लेकिन इसको लोकमत जानने के लिए भेजा जाये, इसका मैं समर्थन करती हूँ। एक बात मैं और भी यह कहना चाहती हूँ कि अभी जो खर्च के बारे में पाबन्दी है उसको ज्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। अगर खर्च की राशि को कम किया जा सकता है तो उसको कम किया जाना चाहिये लेकिन जहाँ तक इस पाबन्दी का सवाल है, इसको सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये। मैंने देखा है कि बहुत से उम्मीदवारों की उम्मीदवारी कानून का ठीक तरह से पालन न होने की वजह से रद्द हो जाती है। अगर हम इस पाबन्दी को नहीं रखेंगे कि इतना खर्च होना चाहिये और हर एक उम्मीदवार को उसका हिसाब रखना चाहिये तो लोग इस पाबन्दी के न होने की वजह से बहुत ज्यादा खर्च करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए आपके सामने जो संशोधन है, उसका मैं विरोध करती हूँ।

SHRI MOHAN LAL SAKSENA (Nominated): Sir, I have heard the speeches of the mover and some of the supporters for circulation of the Bill to elicit public opinion. I am neither in agreement with the Bill nor with the motion for circulation of the Bill, and for very good reasons. Soon after the General Elections I had written as to what had happened during the elections; I had written a few articles on them. Of course, it was a matter for some satisfaction that the biggest democracy, as ours is, has been able to have three general elections, and the election machinery has more or less worked satisfactorily. Apart from that, it could be noticed, not only in this election but in the last general elections also, that there were a number of malpractices which were committed with impunity, which were not taken notice of, which could not be checked either. Even before the Third General Elections I had drawn the attention of the authorities to these and suggested several measures to that end. After the General Elections, as I have said, I

had suggested three measures. One was that the Government should appoint a high-powered commission to examine the working of the third General Elections and find out the lacunae in the election law in the light of the last elections and to suggest amendments to provide against a recurrence of these malpractices, as well as to go into the question and find out how the election expenses could be reduced.

The second suggestion was that an all-party organisation should be set up, which should formulate a code of conduct for parties and candidates. The political parties may have different policies and programmes, but they have the common objective—the maintenance of country's integrity, preservation of its security and the well-being of the people. To that end all the parties profess to work, and I am glad at least one amendment was made in the Constitution, that every candidate has now to take an oath before filing his nomination paper that he believes in the integrity of India.

Then, the third measure I had suggested was that there should be an integrity commission, a statutory integrity commission—which should work like the Election Commission of India—under the President of India, and enforce certain duly defined standards of integrity in administration as well as public life. All these measures, if they could be taken, if the suggested commissions and the committee could have been set up, they could at least have examined the situation and might have suggested the necessary measures to safeguard freedom and democracy in this country.

I have no doubt, as I have said once before in this House, that the last general elections have brought democracy into disrepute in this country; they revealed certain shortcomings in our election law as well as certain dangers to democracy. After all, democracy is only a means to an end,

and the end is well-being of the people. And unless we can assure that, I feel political parties will prove a costly purse, instead of being a necessary evil, as they are supposed to be in the parliamentary system of democracy. I had suggested how the election expenses could be reduced. Now, what are the items on which expenses are incurred? First of all it is necessary that every voter should know that a particular person is standing as a candidate. Next, the people, the voters should know to which party he or she belongs, and what are the policies and programmes of that particular party. Thirdly, the candidate should get into touch with as many voters as possible. Lastly, there were the polling day expenses—different candidates set up separate camps at polling booths and that also costs a lot. So my suggestion was that, instead of every candidate keeping an account of his election expenses—which to some extent is difficult to do—it would be much better—as is the practice in some countries—that once the candidates are nominated, an all-party committee consisting of all the candidates or their representatives and presided over by a representative of the election authorities is set up to regulate these election expenses. The candidates are required to deposit a certain amount with the committee. Then this committee decides as to how many leaflets were to be issued, how many posters were to be issued and how many meetings were to be held.

As for the polling day, it is not necessary that each and every candidate should set up a separate camp. And why should it be? After all it is the business of the polling authorities to see that all the voters who come to the booth are properly conducted and have full facility to cast their votes. So, if this committee consisting of all the representatives of the candidates and presided over by a representative of the election authorities, could decide about the propriety of the election expenses, the

expenditure could be reduced and there could be a check on it also.

Not only that. I can also appreciate the difficulty of the candidates. Mr. Bhargava has pointed out that once a candidate is nominated, his only concern is to see that he is elected. I do not think it should be the concern of the candidate. The first concern of the candidate should be to see that the people are properly educated if we are to serve the cause of democracy; it is not to see that one particular candidate or person is elected. What does it matter if a person is elected or not? Now, if you examine the record of the last two general elections, you will find that precious little has been done for the education of the voters.

3 P.M. Now people deliver some routine speeches. And instead of the people visiting the voters from house to house, aeroplanes are used to drop notices or hand-bills. That may be a good device for demonstration which may influence the voters who may be carried away by it. But that is not educating them. Unless you educate the voter, I am sure democracy will always remain exposed to danger and anything might happen. So my suggestion is, as I had also suggested during the course of the general discussion on the Budget immediately after the Third General Election, that a high-powered commission should be appointed immediately to go into the working of this election law, to see that the polling process is not only made foolproof but also knave-proof.

Mr. Bhargava has pointed out that if a person so chose, he could incur all the expenses before the date of the announcement of the election and defeat the provision regarding filing of election expenses. He could pay for the petrol, printing, conveyance etc. beforehand. If you do that, the purpose of any law can be defeated. It is not like that. Our purpose here is to see how the law can be enforced if it is a necessary law, if it is a useful law. If it is not, it should be

[Shri Mohan Lal Saxena.]
scrapped straightway. From the Bill, it appears that Mr. Bhargava wants that this chapter on the election expenses should altogether go.

Sir, there is also a drafting error which has not been pointed out. I might point out that Mr. Bhargava has sought to repeal three sections of chapter 8, I think 76, 77 and 78. He has also sought to delete one of the provisions in one of the clauses in section 123. There is another clause which relates to the election expenses. In his Bill he has not sought to delete it. Even if these two are given effect to, corrupt practices, as defined in sub-clause 6, will continue. Therefore, it is not a question of election expenses alone. Are we not aware that many corrupt practices have been committed during the last elections? To cite only one instance, which has been cited before, the use of conveyance, the use of vehicles. We know it is a corrupt practice to provide vehicles to take the voters to the polling booth and back. Still we know that this provision is being defeated with impunity. Cases are known of vehicles coming from Kashmir to work for the elections. What is all this? Either we permit or we do not permit the use of vehicles for conveyance. If we do not permit, as I think we should not, then the only course is instead of having polling booths situated at long distances we should have more polling booths and we must see to it that conveyance provided by a friend or anybody should not be used; it should be taken as a corrupt practice. This gives advantage only to the person who can borrow conveyances from his friends, instead of paying cash, and use them for the voters.

Sir, under the Constitution we have guaranteed equality of opportunity. Our Constitution provides for a democratic form of Government, a parliamentary democracy. Therefore, we must see that every candidate, everybody gets equal opportunity. Mr. Bhargava has suggested the removal of

provision for filing return of election expenses. He said, let the candidate spend to his heart's content. I do not know where he got that idea from. I think in that connection Gandhiji was also quoted. 'Satyameva Jayate' was also referred to, and he said, therefore, we must do away with it. Personally, I might remind the House that Mahatma Gandhi, even a few months before his death, had reminded us that democracy was becoming very costly and unless we reduced the expenses and made it a poor man's affair, it cannot last long. People will get fed up with it soon. I know since 1948 things have become much worse.

Gandhiji's idea was that in a free democracy many parties and persons will woo the voters but only the best persons should win. But then in 1948 he emphasised that the Congress should cease to be a political party and it should only see to it that no faked voter is brought on the voting register and that the voter gets the proper opportunity of understanding the issues placed before him and of exercising his vote freely. So, that was his idea of democracy.

Sir, there is guided democracy, there is controlled democracy, there is basic democracy and so on.

SHRI N. M. LINGAM (Madras): People's democracy also.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: But we are committed to the parliamentary system of democracy. And if the parliamentary system of democracy is to work successfully, that is, in the interest of the people and not in the interest of the candidates or a few persons who may be at the top, it has to be worked in such a way that it does not become a costly affair.

SHRI LOKANATH MISRA: I can just add here for the information of the hon. Member that 'Satyameva Jayate' has been replaced by 'Arthameva Jayate'.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: It might have been replaced, I do not know. But it still remains our national motto. Therefore, I agree with him that we must take every step to see that we are able to comply with the rules and provisions. But if we look to the convenience of the persons fighting an election, convenience of candidates, I am afraid we will never be able to act up to this motto, 'Satyameva Jayate'. I know, Sir, not only in this sphere but in many other spheres how the laws are enforced, how people make distinction in telling truth before a court and in telling truth in their day-to-day affairs. Therefore, for that we have to set a standard and stick to it. For unless we stand by that standard, however irksome it may be, though we may fail to win a seat, unless we hold fast to that standard, I am sure we will not prove worthy of it. It will only add to the evil because the danger, as I have pointed out earlier here in the House, the greatest menace to democracy is the money menace. Money should not come in. And what do we find today? It is money at every stage which is dominating.

Here I am reminded of the observation by Swami Vivekananda: He said, "What would happen if India were to die? All the love for religion and spirituality will disappear and in its place will reign the duality of lust and luxury, with money as its priest, force and fraud will be the ceremonies and the human soul will be the sacrifice". So if you want to strengthen parliamentary democracy, you have to hold fast to this ideal. After all, even before we had independence we had this law. We also had to file election expenses returns. I have been in this affair since the formation of the Swaraj Party. I was one of the founders of the Party, and I can tell you without fear of contradiction that we took particular care to file our election expenses returns then and there. But then there was a method about it. We decided as to how much was to be spent on transport, how much was to be spent on publicity

and all that. Having done that, it was not difficult to keep accounts. I can understand that it is not easy to get all the vouchers. For that we can make a provision that vouchers for Rs. 25 and less may not be produced subject to the provision that the total of such expenditure did not exceed 20 per cent. of the total amount spent. That is a genuine difficulty and should be looked into. We know even in the Rajya Sabha election, where we are not to file any return of election expenses, how money has been spent, how it has played a prominent part—I would not say havoc—has been utilised for winning votes. There is no question of educating the voters. After all, the members of legislatures are themselves educated. But we know how selections are made by one group in the Congress. Even in the elections of party leaders these practices have resorted to. Once we give a licence, once we allow this loophole here, I think we open the floodgates to all kinds of corruption. Therefore I am one of those who believe that this Bill seeks to provide a remedy worse than the disease.

Now, as regards money, not only now but since 1951, before the First General Elections, I had been of the view that no Party should raise big sums from any person and in that regard I had suggested that only active members of a party should be allowed to contribute Rs. 5,000 or Rs. 10,000 at the most to the party funds and as the Lady Member said just now, I had suggested then that proper accounts should be kept of every pie that is received; but now what happens is, it is the Chief Minister or somebody else who receives the money and who disburses it at his pleasure. It does not go even to the Party . . .

SHRI LOKANATH MISRA: And disburses a part of it.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: I do not know. That may apply to other parties as well but I say that all these evils arise from these big donations. They were not made with

[Shri Mohan Lal Saksena.]

any ulterior motives or considerations. It is for some end that this money is spent and therefore I had suggested then and the Prime Minister who had taken up the Presidentship of the Congress, had accepted my suggestion and it was decided that the Congress Party should collect money in small donations. I do not mind collecting money. Of course, as Mr. Yajee has pointed out, every party has to raise funds for running it but where does it get from? The larger the number of people that contribute the more popular it is and the less expenditure you will have to incur during the elections. If you can go and make people contribute one rupee each for your elections, I am sure that the person is sure to vote for you whether you go to him or not. If it is not a voluntary contribution, I am against it.

Then the whole question is this. I suggested and the Prime Minister accepted the suggestion and receipts were printed and the State Committees were expected to co-operate with it but the then Treasurer, Shri Morarjibhai, of course did not favour the proposal. He referred to it in this House during the Budget discussion, you will remember, and he said, "I have had sad experience of the suggestion". Then I got up and said, "This was my suggestion and I took responsibility. I have got correspondence with me". I said, "What is it"? and then he said, "Yes, you wrote that it failed. It failed because the State Committees did not respond. You should have foreseen that it will not work". I said, "It was not a question of the State Committees not responding. I had no power to work the scheme. I had only made the suggestion and the President had accepted it and if you did not feel that it would work, you should have told him or others should have told him, but nobody told him and ultimately it was discarded and he said that it had failed". It did not fail for want of response on the part of the State Committee or workers on the lower ranks

but because the top people thought it was easier to get big sums than to go about making collections. So ultimately when it came to this, he admitted: "Well, I do not want to go into further correspondence"; but I said, "You have made a statement in the House. I owe to the House to explain it and to bring it to its notice what was wrong with my suggestion with which you had differed" and then he said, "I would not have even replied if I had known that you were going to publish it". What is it? I would like to read this portion in which I had said: "I am glad at least I could foresee the evil flowing from big donations that you are facing today". If we had not collected these large sums, we might have lost a few seats but I am sure the prestige and the honour of the Congress would have remained untarnished and these allegations that are being made, not by members of the opposition parties only but also by members belonging to the Congress—fingers of accusations have been raised by equally responsible Congressmen—against Congressmen, this would not have happened. What does it matter if we lose a general election? The Congress which could fight a foreign power, get into power, I am sure, can dislodge any party which comes into power if it loses the elections on principles, not on persons or other issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): You have given the purport of it. Is it necessary to read it?

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: I would like to because I do not want anybody to say that I have been unfair to him. I would like somebody to read it—only one portion . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): No, you have to read it. Nobody can read it for you. But you have very elaborately explained it. It is not necessary to strain yourself by reading it.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: Having said that, I am still opposed to these big donations being given either by institutions or by companies, as has been permitted under the Company Law for the simple reason that it is the money of the shareholders. If 'A' or 'B' is interested in boosting up or supporting a particular party, he may contribute but not out of the funds of a particular concern. That is why I had made a definite suggestion that it is only active members who should be allowed to give more than Rs. 10,000 and for the expenses receipts should be obtained.

Now, you are aware that after the Kamaraj Plan there is a Committee working in the A.I.C.C. to lay down some rules regarding collection of funds and their disbursement. I hope that Committee will consider and keep in mind the past experience and will devise ways and means to set an example to other parties, not only to regulate collections or to set its house in order. I am one of those who believe that it is the duty of the ruling party because there is no other party in this country which can rise equal to the occasion or which can replace it. It should not only run the administration and the party organisation in such a manner as will win the admiration of others—even of the opposition parties. Therefore, I submit that in the first place, the Government should set up a high-powered commission to examine the working of the election laws and to make recommendations as to how these loopholes can be plugged to avoid a repetition of the malpractices and the play of money as we have seen during the past two elections. That is one suggestion.

The other suggestion is that there should be a Code of Conduct for the parties as well as for the candidates. Unless we have that, we cannot enforce anything. After all, there is the U.N. Organisation where we have Soviet Russia and America working together for years now. They have their own views, they have their different approaches but still they have some

agreed principles on which they have to make certain approaches to world problems. Similarly my suggestion is, let the leaders of the parties come together. I am sorry Dr. Rajendra Prasad is dead and I had hoped that he could very well play this role; he could do that very well but it was not the will of God that he should be with us. So, even then it is the responsibility of everyone who had worked under Mahatma Gandhi, who has derived inspiration from him and everyone of us swears by his name and refers to him again and again, but let us not forget his ideas and ideals, and what are they? I had made suggestions and one of the suggestions was that Mahatma Gandhi's name should not be used by any party even as they are not permitted to use the national flag or other national symbols because Gandhiji's name is a national symbol and he was the Father of the Nation. What does it mean?

SHRI LOKANATH MISRA: The Congress uses it as it pleases.

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: I say that it should not be allowed. It should not be allowed because after all it is the national symbol.

There are electoral offences and malpractices, that nobody should appeal in the name of castes or communities and all that, but we know that not only appeals are made but also candidates are set up and considerations of castes and communities are given due weight by all the parties. Not only that, candidates are set up simply to divide the votes of particular castes or communities, with the result that there are so many candidates and therefore the interests of the voters suffer. We have a law to regulate the working of Trusts. We have a law to control the working of companies and so on. These laws are designed to safeguard the interests of shareholders holding shares of Rs. 10. But is there any law to safeguard the interests of the people in this matter, to safeguard democracy and freedom? Is it not

[Shri Mohan Lal Saksena.]

necessary that there should be a law to regulate the formation and functioning of political parties—Congress party or any other party? There should be that law. Unless we have such a law, I am afraid, the way parties are working, shows we are on the downward trend. During the last ten or twelve years, no party has gained in stature or strength. Even the Congress party during the last elections has lost more seats than in previous elections. The number of seats that the Congress party lost in the Second General Elections was larger than the number that it lost in the first General Elections and it lost a still larger number in the Third General Elections. What has been the position? If five voters voted in favour of the Congress, six voted against it. If that is the position, is it democracy? In a democracy, if the people want a particular party to be in power, that party should be in power. It is not because of the strength of the Congress party that it has won majority but because of the differences in the opposition parties. Therefore, I submit that to safeguard the interests of democracy and freedom, to safeguard the interests of the voters, there should be a law to regulate the formation and functioning of parties. It is not only one provision regarding election expenses, as has been suggested in Mr. Bhargava's Bill, that should be re-examined. It may serve as unktion to guilty conscience, but I am sure it is not going to serve as a remedy; it is no remedy and it is no safeguard; it will not serve as a safeguard for democracy or would ensure fair-play in the elections.

With these words, I would like to conclude my observations. I may, however, add that I had even sent a Resolution to this House, but because of the emergency I did not press it. I had sent my suggestions to the Prime Minister and he was good enough to forward them to the Election Commission, because I had given several instances and I had quoted

many cases. I think it is the duty of the Government, of the Party in power—it is not enough if a Member moves a Bill—to come to some definite conclusions, in consultation with other parties, if necessary, and then they should take definite steps in the proper direction. I hope they will act before it is too late.

شرعی عبدالغنی (پنجاب) : جب

میں اس بل کے موور پو نکا کرتا ہوں تو وہ ہندوستان کے عظیم ورکروں میں ایک عظیم ورکر ہے۔ جب میں ان کی اسپرٹ کو دیکھتا ہوں تو وہ گاندھی جی کے اس ارشاد دستہ اور اہلساء کے پجاری ہیں۔ ستیہ کو باپو نے بڑا درجہ دیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ستیہ کا ایک ایمان ہوتا ہے جو یہ ایک لیمنٹ رکھی ہے تو کافی مجھے دھیاں سے جانا پڑتا ہے اس بات میں کہ ان کی بات میں کافی وزن ہے۔ جب میں اپنے ان معزز ساتھیوں کی تقریروں پر جانا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ستیہ کا ایمان ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اسکو جو ریٹرن دیلے پڑتے ہیں الیکشن کمشنر کو تو اس میں کافی باتوں کو چھپانا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو آج ووٹوں سے آئے ہیں ان میں سے کتنے بھائیوں نے غلط بھائی کی اور غلط بھائی کے بعد آیا ان کو اخلاقی طور پر دھنا چاہئے یا نہیں

رہنا چاہیئے - اس پر جب میں وچاؤ کرتا ہوں تو میں دہتا ہوں کہ شاید بہت سے مجبوری میں مسیروں کو اگر وہ اپنے اخلاق کو سامنے رکھیں تو شاید ان کو ریزائن کرنا پڑے -

میں سمجھتا ہوں بھارگوا صاحب کے اس بل کو ہاؤس کو بڑی شان کے ساتھ پاس کرنا چاہیئے - لیکن مجھے دہ لگتا ہے کہ جس آزادی کے لئے جس تیموکریسی کے لئے ہزاروں خدا کے بندوں نے اپنی جانیں قربان کیں لاکھوں کلہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا شاید وہ ہمیں برباد کرنے کی طرف پہلا قدم فہ اٹھالے - یہ بات یوں میں کہتا ہوں کہ آج تک کا الیکشنوں کا تجربہ جملہ وائس چیمبر میں صاحب جو ہمارے سامنے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے غریب ورکر ہوتے ہیں ان کو تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں پڑتی ہے - اور اگر کسی غریب ورکر کو کوئی پارٹی ہمت دلائے ، اتنا دلائے تو وہ کہتا تو ہو جاتا ہے لیکن جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتا وہ ایک ایک دن کس طرح بتاتا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے - کیوں کہ آج کا الیکشن بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے اور کوئی ورکر اس شان کے ساتھ جس شان کا وہ مستحق ہے جو اس کے پہلے کا گذرا ہوا زمانہ ہے اس کو

قربانیاں ہیں اس کی کتنی قیمت قوم کو دینی چاہیئے یا ورکر کو دینی چاہیئے یہ خاصہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طوفان میں جو تمام پارٹیاں ایک دم سے بڑے زور سے روپیہ بہاتی ہیں تو لاکھوں ورکر بے بس ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان کے پاس سادھن نہیں ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں - پھر یہ دھیان جاتا ہے کہ جو یہ قیمت مقرر کی گئی تھی اس وقت اس کی جو قیمت تھی آج شاید اس کا ۲۵ پر سنٹ بھی قیمت نہیں رہی کیوں کہ حالات نے نہ صرف کنوینس کو مہنگا نہ صرف پرنٹنگ کو مہنگا کیا نہ صرف اس بات کو کہ وہ کس طرح سے اپنے جاسوس کا انتظام کر سکیں کیوں کہ ان کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا بلکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئیں تو وہ چاہے ورکر ہو چاہے کاریہ کرتا ہو غیر سرکاری ہو سرکاری ہو اس کو بالکل ایک مجبوری کی حالت میں رہنا پڑتا ہے - اور بہت خرچ کرنا پڑتا ہے - تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس قیمت کو جیسا کہ انہوں نے کہا آڑا دینا چاہیئے کہ کوئی ریٹرن ہو کر دیا جائے کہ اتنا خرچ ہوا - کافی حد تک مہرا ان کے ساتھ خیال کیا جاتا ہے لیکن پھر دہتا ہوں کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ایک اچھا آدمی یا ورکر

[شری ابدالغلی]

جس سے دیہی کا ہمت ہو جو کہ
دیہی کی عزت اپنے کلدھوں پر لیلے
کے لئے تیار ہو اور الیکشن لڑنا چاہے
تو کہیں یہ پابندی ہٹائے کے بعد
اس کا راستہ اور زیادہ مشکل نہ
ہو جائے۔

وائس چیرمین صاحب - یہ ایک
بڑا گہرے مسئلہ ہے اور ہمارے دیہی
کا جو آنے والا زمانہ ہے اس سے اس
کا بڑا تعلق ہے اس لئے میں کافی
ذمہ داری سے اس پر وچار کرتا
ہوں۔ مجھے جو تجربہ ہوا وائس
چیرمین صاحب - میں نے پچھلے
دنوں ہاؤس میں کہا تھا اور میں
کسی ایک پارٹی کے لئے نہیں کہتا
سب کے لئے کہتا ہوں۔ اپنے آپ
کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ دیہی
سب میں بڑا ہے یہ ہمارے ذہن
میں آئے اور ہم دیہی کو بچائیں
کئی باتوں میں ہم پارٹی کو بڑا
مانتے ہیں۔ اور اس کی حد سے
آگے نکل جاتے ہیں اور ہر آدمی
یہ سمجھتا ہے کہ میرو ہستی
کو پارٹی سے ترجیح دیتا ہے اور اپنے
آپ کو بھول جاتا ہے۔ کاش -
میں اس بات پر اپنے ان نہتوں کو
راضی کر پاتا جو دیہی کی باگ دوڑ
سنبھالے ہوئے ہیں اور آگے بھی سنبھالنے
کی فکر میں ہوں۔ تر میں یہ عرض

کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک
ہندوستان میں اتنی زیادہ تعلیم نہ
پھیل جائے جب تک لوگ پوری طرح
پر سیاسی ماحول سے واقف نہ ہو
جائیں اس وقت تک ہمارے دیہی
میں ایک اچھی گورنمنٹ نہیں بن
سکتی جو اچھے آدمی اس میں آ
سکیں انہیں لیا جائے۔ جو اچھے
آدمی ہیں اگر وہ آتے ہیں تو انہیں
اس بات کی فکر نہ ہو کہ کونسی
پارٹی ہوگی جو رول کرے گی اور
کس پارٹی کی مرضی کے مطابق ہم
کو چلنا ہوگا۔ کاش میں اس بات پر
راضی کر پاتا اپنے نہتوں کو جو ہمارے
ووچہ بایو کی باتوں کو بھول گئے
ہیں جو کہ مہاتما گاندھی چاہتے
تھے۔

مجھے بڑی خوشی ہے کہ سکریٹری
صاحب نے ایسی تقریر میں یہ کہا
کہ کسی بھی پارٹی کو دیہی میں
مہاتما گاندھی کا نام استعمال نہیں
کرنا چاہیئے ایسی کامیابی کے لئے اور
دوسروں کو ناکام بنانے کے لئے۔
لیکن میں اس اگست ہاؤس میں
کہتا ہوں اور میں ایمان داری سے کہتا
چاہتا ہوں کہ مہاتما گاندھی نے
دماغ میں یہ بات تھی کہ اس ملک
میں ہریجنن بیگنی پرائم منسٹر بنے
اور راجگڑ پتی بلے تو ان کے دماغ میں
جو اس طرح کی بات تھی۔ اگر
ہمارے ملک کے نہتے ایسا رنگ پھدا

کروں اور لوگ یہ نہ دیکھ پائیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون نیچے ذات کا ہے اور کون اونچے ذات کا ہے تو اس سے ہم ایک نئی فضا ملک میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے دماغ میں جو یہ سب سے بڑی بات تھی کہ ایک ریجن لڑکی ملک کی پرائم منسٹر یا راشٹری بلی تو ان کی منشا یہ تھی کہ ہمارے جو الیکشن ہیں۔ اے جو چناؤ ہیں وہ ہر طرح سے برائی سے پاک ہوں، ہر طرح کی مشکلات آسان ہوں اور ہر ایک کے لئے یہ چانس ہو کہ وہ اپنے دیس کی خدمت جس طرح چاہے کر سکے اور اس چیز کا اے پورا موقعہ دیا جائے۔

میں اس طرح کی اسپرٹ نہیں لا سکتا ہوں اور نہ میں کسی کو راضی کر سکتا ہوں لیکن دیس سب سے بڑا ہے اور باقی چیزیں اس کے نیچے ہیں۔ ہمارے جو بڑے بڑے نہتے ہیں بڑے بڑے آدمی ہیں وہ سب دیس کے لئے ہیں دیس ان کے لئے نہیں ہے۔ دیس سب سے بڑا ہوتا ہے اس لئے میں نے پچھلے دنوں ایک بار کہا تھا۔

اک تھکے کل کے لئے کل تھکے پورے ہوتے۔ پورے تھکے ہت دیس کے۔ دیس تھکے جگ ہیٹ

اگر ایک خاندان کو بچانا ہے تو ایک آدمی کو قربان کر دو۔ اگر ایک

لوگوں کو بچانا ہے تو خاندان کو قربان کر دو۔ اگر دیس کو بچانا ہے تو لوگوں کو قربان کر دو میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ بھڑال کرشن نے کہا ہے کہ اگر دیس واپسی کسی کو اپنی آتما کا خون کرنے کو کہتا ہے تو وہ دیس کو بھی چھوڑ دے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میں بہارگوا صاحب سے متفق نہیں ہوں اور میں اس بل کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وائس چیرمین صاحب کہ اس سے برائی کا حل نہیں نکلتا۔ وہ لوگ جو اسمبلی اور پارٹی کے ممبر بنتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جتنی رقم الیکشن میں لڑنے کے لئے قانونی طور پر مقرر ہے اس سے کہیں زیادہ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے ان کو جب اسٹیٹمنٹ داخل کرنا پڑتا ہے تو وہ چھوٹا اسٹیٹمنٹ داخل کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں لٹا راستہ ہے۔ راستے دو ہی ہو سکتے ہیں یا تو آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ صرف اسمبلی کے لئے اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو اور اس میں وہی لوگ جائیں جو کہ ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں اور جو غریب آدمی ہے چاہے کتنا ہی قابل کہوں نہ ہو چاہے کتنی ہی لیاقت کہوں

[شری عبدالغلی]

نہ رکھتا ہو اس کے لئے کوئی چانس نہیں ہے آپ بھی یہ مانیں گے کہ سرکار چاہے کوئی بھی ہو اس کو بھی انڈسٹریلسٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، سرمایہ داروں کا سہارا لینا پڑتا ہے بڑے بڑے بزنس مینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اگر میں غلط نہ کہوں تو کئی جگہ تو وہ اپنے اختیارات کا نا جائز فائدہ اٹھاتی ہے۔

وائس چیمبر مین صاحب میں نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر نے لاکھوں روپیہ جو پچلے الیکشن میں اکٹھا کیا تھا اپنے پاس ابھی تک جمع کر رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روپیہ مجھے الیکشن فلڈ میں دینا گیا تھا اور میرے گھر میں پڑا تھا۔ پتھریوں میں پڑا تھا اور کافڈوں کے بلڈلوں میں پڑا تھا اور اب میں دو برس کے بعد اس کو واپس کرنے جا رہا ہوں وہ اب دلیر بن گئے کہ لوگوں کا روپیہ دو برس بعد واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اسمبلی سہت کے لئے تو سات ہزار روپیہ قانونی طور پر ایک آدمی خرچ کر سکتا ہے تو انہوں نے اتنا روپیہ کہوں اکٹھا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پارٹی فلڈ کے لئے یہ روپیہ دیا گیا تو یہ روپیہ پارٹی کو کیوں نہیں دیا گیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ سب پارٹیوں کے لئے دیا گیا تو سب پارٹیوں کو

کیوں نہیں دیا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک عجیب رنگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو خرابی کا باعث ہوگا۔

آخر اس کا کیا حل نکالا جائے۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں انور صاحب کی عظیم الشان تقریر کو نہیں سن پایا لیکن میں سمجھتا ہوں وائس چیمبر مین صاحب! کہ بھارگوا صاحب جو ہمیشہ بلند خیال رکھتے ہوں۔ جن کی نیت بلند ہے جن کی عزت میں ہمیشہ کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا رنگ پیدا کریں کہ جس سے ڈیموکریسی قائم رہے۔ چروٹے لوگ بھی اُگے آسکیں۔ چھوٹے لوگ آزادی سے رائے دے سکیں۔ اگر اس طرح کا کوئی سادھن ہو سکتا ہے تو انہیں لانا چاہیئے بجائے اس کے کہ یہ ایمیلڈ مہنت لائے۔ انہیں تو اس طرح کا ایمیلڈ مہنت لانا چاہیئے تھا کہ آل انڈیا ریڈیو سے سب پارٹیاں اپنا میسجسٹو تیار کرے، اپنی خوبیاں بتا کر اس کو براۓ کاسٹ کریں کہ اس طرح کے ہمارے ورکر ہیں اور طرح کے امیدواروں کو ووٹ دیں ہمیں آل انڈیا بھیسز پر سب پارٹیاں کو ایک اس طرح کا پروگرام بنا لینا چاہیئے جس سے وہ ملک کے لوگوں کے سامنے اپنی پارٹی کا پروگرام رکھے

سکھیں - اگر ہم ایمرجلسی کے سامانہ
میں ایک جگہ اکٹھا ہو سکیں تو
ہم پھر اس بات کا خیال نہیں
کرتے کہ جو آلے والے الیکشن میں آئے
میں صرف پارٹی کا پیغام ہو اور ووٹروں
کو کھلی چھوٹ دی جائے کہ وہ
آدرشوں پر جو لوگ آئے ہیں انہیں
ہی ووٹ دیں - اگر سب کو یہ بات
منظور ہو تو شاید ہی کوئی ٹکڑا ایسا
ہوگا کوئی دیہات ایسا ہوگا جہاں کہ
آل انڈیا ریڈیو کی آواز نہ پہنچتی
ہو - تو اس کے ساتھ ہی ساتھ سب
پارٹیوں کے نمائندوں کی طرف سے ہندی
میں ریجنل لیگسلیچر میں اور
انگریزی میں یہ نکل دیا جائے کہ ہم
یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ
لوگ ووٹ دیں اگر ہم اس طرح کے
پمفلٹ پوسٹ آفسز کے ذریعہ لوگوں
کے گھر پہنچا دیں تو نہ ہمیں پھلک
میٹنگ کرنی پڑے گی اور نہ ان
میٹنگوں میں گرما گرمی آئے گی؟
نہ ہم گندے اشتہار نکالیں گے نہ ہم کسی
دوسرے پر حملہ کریں گے اور سب
لوگ اس بات کی چرچا کریں گے کہ
ہم نے فلاں کو چن لیا ہے اس میں
یہ اچھا نہیں! میں اس کو ووٹ دینا
چاہیئے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا
کھوں نہ ہو - جس دن ووٹ پڑیں گے
اس سے ایک مہینے پہلے نہ کوئی
جلسہ ہو نہ کوئی اشتہار بازی ہو نہ
کوئی افسر کسی کو کوئی پرمٹ دے -
نہ کسی کو لائسنس دے نہ اور کسی

کو اسٹیشنل سارٹیفیکٹ دیا جائے اور
نہ ہی کسی کو قبضہ دیا جائے - اگر
ایسا راستہ نکال دیا جائے تو میں
یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ ہمیں
۲۵ ہزار خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی
اور نہ ۷ ہزار خرچ کرنے کی ضرورت
پڑیگی - یہ میں کہوں کہتا ہوں -
آخر ہم سب دل و جان سے - کرنی
بھی پارتی ہو مہرا یقین ہے کہ
قیموکرسی میں سب کا ایمان ہے -
چاہتے ہیں کہ قیموکرسی رہے -
تو کوئی اس کا سادھن کھجئے ورنہ
کوئی برائی ایک ہے؟ آپ جانتے
ہیں کہ صرف روپے کی ہی برائی
نہیں ہے - روپے کی بھی برائی ہے -
ایلی آتا کا خون کرنا پڑتا ہے جب
کوئی ریفرن دیتا ہے - اس کو پتہ
ہوتا ہے کہ میں نے ۲۵ ہزار کی جگہ
۷ لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے -

بڑے بڑے نمائندوں کی بات نہیں ہے
جو مہرے پہلے بھی آنریبل ممبر بولے
انہوں نے کہا کہ کچھ نمائندوں کو چھوڑ
دو - باقی تو سب تھوڑا خرچ کر کے ہوتے
ہیں - میں جانتا ہوں کہ ایک زمانہ
میں جب کانگریس کسی کے ماتھے
پر لکھ دیتی تھی کہ یہ آپ کا خدمت
گزار ہے اور ہم ابھل کرتے تھے کہ لوگ
اس کو ووٹ دیں تو مجھے یاد ہے
کہ بڑے بڑے راجہ، بڑے بڑے امیر
لوگ، بڑے بڑے بھرسٹر لوگ،
بڑے بڑے زمیندار لوگ ایک
فریب سے فریب کے مقابلہ میں ہار

[شری عبدالغنی]

جاتے تھے لیکن آج مجھے تو ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خدا نہ ہو جائے۔ اگر پلندے جواہر لال نہرو بھی آج ریڑائن کر کے مقابلہ کریں تو شاید وہ بھی ہار جائیں۔ دنیا کے حالات بدلے رہتے ہیں اور آپ وہ تھلکھنگ اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کیجئے۔ انگریزوں کے مقابلہ میں یقیناً کانگریس ملک کی ایک واحد نمائندہ جماعت تھی اور اس میں سب پارٹیاں شامل تھیں چاہے وہ سوشلسٹ ہوں چاہے پرچا سوشلسٹ ہوں چاہے سونلتر ہوں چاہے جن سنگھ کے بھائی ہوں چاہے اکالی ہوں۔ چاہے کمیونسٹ ہوں وہ سب کے سب کانگریس کے جھنڈے کے تلے تھیں۔ یہ بات الگ ہے کہ جب ہم نے آخری جنگ لڑی تو اس وقت کمیونسٹ بھائیوں کا دماغ پھپھس وار کی طرف چلا گیا تھا لیکن یہ سچ ہے کہ اس میں سب کے سب شامل تھے اور کانگریس ایک بڑی طاقت تھی۔ کانگریس ملک کی آزادی کے لئے تھی ملک کانگریس کے لئے نہیں تھا۔ اگر یہ بات درلنگ پارٹی کے دماغ میں آجائے جو اس وقت اکثریت میں ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہئے کہ پتہ نہیں ہم پانچ برس چھٹھیں دس برس چھٹھیں لیکن اس دیکھ کو سدا رہتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک

دنیا کا ناہی نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو سوچنا ہے کہ الیکشن کا دھنگ کیا ہو۔ اور اس کو آپ جتنا سادھارن کر سکیں اتنا اچھا ہے۔

بھارگوا صاحب جو ہل لائے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ الیکشن کھیلنے کی اس پر کیا رائے آتی ہے لیکن میرا یقین ہے کہ اگر یہ تھوک ہے تو اس کو سب پارٹیوں کو سامنے لانا چاہئے۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ اتنے دھڑے سونلتر پارٹی جو دنوں میں خاصہ بڑے کئی وہ کہیں بڑے کئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دولت کے زور پر بڑے کئی اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ائینتہالوجی کے زور پر بڑے کئے۔

وائس چیمبرمیں صاحب۔ اس وقت کانگریس جو سب سے بڑا اپنا دھبہ مانتی ہے وہ سوشلزم کا دھبہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا رنگ جمایا جائے جس میں کافی ایکٹنا آجائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ قریب اور امیر کا فرق جو ہے کم ہو جائے۔ آج کئی جگہ وہ غریب سو گنا کا ہے کئی جگہ تیس گنا کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل معمولی رہ جائے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی ایک بڑے افسر کی تنخواہ میں اور ایک چھوٹے سپاہی کی تنخواہ میں دس گنا سے زیادہ فرق نہیں پوتا۔ تقریباً دس گنا پوتا ہے۔ اگر

کانگریس دل سے کہتی ہے کہ ہم سوشلزم لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بات کی طرف آئیے کہ یہ خرچہ جو الیکشن کا ہے یہ قطعی ختم نہ ہو لیکن یہ نام ماتر رہ جائے اور نام ماتر بھی ہوں رہ جائے کفذاتی طور پر کوئی کنڈیڈیٹ بالکل اپنا خرچہ نہ کرے۔ اس کی قربانی یا اس کی قابلیت یا اس کی خدمت یا اس کی ہمت ان چاروں باتوں میں لوگ احساس کریں کہ اس کے جانے سے ہمارے دیس کا بھلا ہوگا۔ اگر یہ بات ہو جائے تو میں بھارگوا صاحب کو جلسوں نے ایک نیا راستہ دکھایا ہے مبارک باد دونکا۔ ایسی صورت میں دیس انچا آئے گا دیس میں ایک ابھار آئے گا دیس میں یہ خیال آئے گا کہ دیس ہمارا ہے اور چائنا کیوں نہ ہو پاکستان کیوں نہ ہو، رشہا کیوں نہ ہو، امریکہ کیوں نہ ہو ہم سب کا مقابلہ کر پائیں گے۔ کیونکہ اس وقت سب سامنے سب سے پہلی قسم یہ ہوئی، یہاں آکر نہیں، کھڑے ہونے سے پہلے اسدولہا جو بنا ہے اس کے سامنے کہ ہم کو اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے، اپنی پارٹی سے، دیس زیادہ پیارا ہے۔ جب اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے اور اخراجات کی بالکل ممانعت کر دیں گے تو میرا یقین ہے کہ صرف پارٹیاں رہ جائیں گی جو ہرجا کر رہیں گی۔

یہ میں مانتا ہوں کہ بہت کٹھناتیاں ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں وائس چیمبر میں صاحب حکم دیتے ہیں کہ آج ایک طرف ہرے بلب پر انکلی رکھیں اور جو نوز والے ہیں وہ لال بلب پر انکلی رکھیں اور جو نوٹرل ہیں وہ فلال بلب پر انکلی رکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ آج ایسا ممکن نہیں کہ گڑوں میں ہم یہ انتظام کر سکیں اور سارے دیس میں پانچ مذت میں ہی سب طے ہو جائے اور کسی پر کسی طرح کا بوجھا بھی نہ پڑے۔ لیکن اگر مجھے معاف کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ پیچھے الیکشن میں قبل بھلت پیپر چھپے۔ ان کے چھپنے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ جس طرح آج کوئی جعلی نوٹ شائع کرے تو اس کی ذمہ داری کانگریس سرکار پر نہیں ہے، فائنلنس منسٹر پر نہیں ہے، ریزرو بینک نے گورنر پر نہیں ہے بلکہ وہ ذمہ داری ہے اس پر کہ جو ایسا کرنا ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی جو قبل بھلت پیپر چھپے میں اس کی کسی طرح سے بھی ذمہ داری الیکشن کمشنر یا ان کے اسٹاف پر نہیں ڈالتا لیکن یہ کہیں ہوتا ہے؟ یہ بات اس لئے ہوتی ہے کہ ایک پارٹی قسم کھائے ہوئے ہوتی ہے چاہے وہ ایجوکیشن پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو کہ ہمیں دوسرے

[شری عبدالغلی]

کو گرانہ ہے۔ اور طاقات میں آنا ہے اس وقت نہ صرف ۲۵ ہزار کی بجائے دو دو لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے بلکہ وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لئے شرم کا باعث بنیں گی۔ اس لئے آپ الیکشن کو سادہ کھجئے اور ایسی کوشش کھجئے کہ جب رائے لی جائے تو اس قہنگ سے لی جائے کہ ایک ہی وقت میں ہر گون میں بجائے اتنا ہوا استاف بھجائے کے یا اگلے بڑے جو یہ جاتے ہیں آپ کے افسر اور ان کا ہوا صلہ اور اس کے انتظام کے لئے پولس اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ جتنے بھی امیدوار ہوں ایک ہو دو ہوں سرکار ایسا انتظام کرے کہ وہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر اکٹھا ہو جائیں اور ان کا ایک ہی وقت میں جو ٹائم مقرر ہو جو بھی ٹائم آپ مقرر کریں اس میں فوٹو گراف ہو جائے اور وہ فوٹو گراف جو ہو وہ سرکار کے پاس پہنچ جائے۔ سرکار سے میری مراد ریٹرننگ آفیسر سے ہے۔ تو اس میں یہ جو ووٹوں کا جھنجھٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی یا کوئی کچھ کہتا ہو کرے کہ اس میں بھی کافی حد تک آسانی ہو جاتی ہے اور بھارتیہ صاحب جو چاہتے ہیں کہ سچائی کا اظہار ہو وہ بھی ہو جائے گا کہ کس

کلیڈیٹ کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ اس طرح ان کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا اور اس ایمرجنسی کے زمانہ میں سرکار کا بھی خرچ کم ہو جائے گا اور سرکار جو ایمرجنسی میں انکمکریشن چاہتی ہے وہ اموشل ہو تو شل ہو یا کسی طرح کا ہو اس کو بھی کوئی دھکا نہیں لگے گا۔

اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے نہتا کن اس بات پر بھی آجائیں کہ جو سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دیس اشوک جی کے زمانہ میں تھا یا اکبر کے زمانہ میں تھا یا چندرگھت کے زمانہ میں تھا اسی طرح سے دیس کو پھر خورشعال بلایا جائے اور جیسا پہلے تھکسلا اور پٹلی پتر کی یونیورسٹیوں کی طرف ساری دنیا آتی تھی اسی طرح پھر سب ہلدوستان کی طرف نگاہیں کھلے لگیں اور ہلدوستان سوائے تعمیر کے تخریب کا نام نہ جانتا ہو اور تب نفرت جو پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے جو دیہات میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے اور جو سچائی چاہتے ہیں بھارتیہ صاحب وہ سچائی بھی ظاہر ہو سکے۔ اس کے لئے اور بھی کئی باتیں اور کئی اسکیمیں ہو سکتی ہیں جس سے سچائی زیادہ ابھرے اور اس لئے ابھرے کہ ہم اپنے دیس کی طاقات میں اضافہ کریں۔

جن نہتاؤں کے ساتھ میرا زندگی کا واسطہ رہا اور میں نے برس ہا برس ان کے ساتھ کاتے آج میں ان سے کہتا چاہتا ہوں کہونکہ ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور ان کے بعد ایوبیہی کے نہتاؤں سے بھی کہتا چاہتا ہوں کہ آخر طاقت کس لئے اٹھتے ہیں؟ طاقت اس لئے لہتا چاہتے ہیں کہ ہم دیہی کو سرو کریں دیہی کی ہم خدمت کریں۔ چلند کلفی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بے شک سارے تالاب کو گندا کردیتی ہیں لیکن ان کی اچھا پوری ہوسکتی ہے سب کی اچھا پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت جو ہوتی ہے ممبران کی وہ ایمان داری سے یہ چاہتی ہے کہ دیہی کا بھلا ہو۔ دیہی کا مانج رہے لیکن آج وائس چیمبر میں صاحب ہمارے پرائم منسٹر جن کا درجہ دنیا میں بہت ہی بلند تھا خدا کرے ابھی بھی بلند ہو۔۔۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : ہ
لہی۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : ہ
لہی۔

شری عبد الغنی : سئلے سے پہلے
ہی آپ بے قرار ہوئے طارق بھائی۔
اور باجی جی میں نے تو ابھی کچھ
کہا نہیں تھا۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : ہم
جانتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے۔

شری عبدالغنی : اس وقت
جب میں نے کہا تھا اور جب میں
نے چیلنج کیا تھا کہ پلڈت جی
دیوائن کریں اس وقت آپ کو چیلنج
قبول کرنا تھا لیکن اس وقت آپ
لوگ سوئے رہے۔ میں جانتا ہوں کہ
آج بھی ان کا ہوا مان ہے۔ اب آپ
خوش ہوئے۔ ایسے عظیم آدمی کو
بھی بعض اوقات اپنی پارٹی کو
طاقت میں رکھنے کے لئے ایسی باتیں
کرنی پڑتی ہیں اور آپ من کے خلاف
اپنی رائے کے خلاف وہ مجبور ہو
جاتے ہیں کہ پارٹی کے لئے ایسی
باتیں کریں جن کو لوگ بالکل
نہ مانیں۔

شری اے۔ ایم۔ طارق : ہ
لہی۔

شری عبدالغنی : آپ اپنی بات
کہہ سکتے ہیں لیکن جو بات میری
ہے وہ میں ہی کہوں گا۔

نکل جاتی ہے سچی بات
جس کے منہ سے مستی میں
نقہہ مصلحت بہن سے
وہ رند بادہ خوار اچھا
میں اعلان سے کہہ سکتا ہوں کہ میں
آج بھی پلڈت نہرو کا زیادہ دوست
ہوں یہ مقابلہ ان کے جو ان کی
باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس
طریقہ پر کرتے ہیں کہ جس سے دنیا
ان کا مذاق کرے جس سے مہذب

[شری عبدالغنی]

دنیا میں سے اور آپ کی چرچا کرے -
اس لئے وائس چیمبر میں
صاحب - میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر
ہماری ٹیم یہ ہے کہ الیکشن میں
جو بھی کاندیدات ہیں ہوں آپ کی
بسم اللہ ہی غلط نہ ہو کہ وہ ایذا دہن
ہی غلط دیں بلکہ ان کی بسم اللہ
تھک ہو تو اس کے بارے میں
ہمیں کچھ کرنا ہوگا - کہیں کہ
جب ان کی بکلیک تھک ہوگی تو
ان کی ایڈ بھی شان دار ہوگی -
اس کے لئے میں آپ کے دواڑا وائس
چیمبر میں صاحب - سرکار سے کہتا
ہوں کہ وہ ایسے سادہ اختیار کرے
جس سے کہ کم سے کم خرچے پر غریب
سے غریب امیدوار بھی الیکشن لڑ سکے
اور مقابلہ میں کھڑا ہو سکے - اس
میں کوئی دقت آئے نہ آئے اور
ایسی صورت نہ ہو کہ کوئی سوتلتر
پارٹی کا راجہ ہو گیا کوئی کانگریس
پارٹی کا نواب ہو یا کوئی جیہ ملک
کا راجہ ہو وہ غریب آدمی کو روکے
کے زور سے دبا دے - تو اگر آپ ایسا
مصلحت دہن کریں کہ جس میں کوئی
غریب سے غریب امیدوار بھی آسانی
سے کھڑا ہو سکے تو بہت بہتر ہو گا -
آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی
جانتے ہیں کہ الیکشن میں ایک
طرف جیپ کی قطاریں ہوتی ہیں
جیسا کہ چائنا کو ہٹانے کے لئے ایک
ہوج چا رہی ہو اور دوسری طرف

غریب کے پاس ایک چھوٹا سا چھکڑا
بھی نہیں ہوتا - الیکشن میں آپ
کے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں -
میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں
کہ جو انہونی بات ہو ایسا ہوا ہے
اس لئے کہتا ہوں - تو بہارگوا
صاحب بجائے اس کے کہ ایڈمٹ
لائن ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ
ایدا خلوص اپنی قابلیت اپنی رزقم
اس بات پر نہیں کہ اس ہاؤس
میں بھی اور جو ہماری لوک سبھا
ہے اس میں بھی اس بارے میں ان
کی آواز پہنچے کہ سچائی اس بات
کا مطالبہ کرتی ہے دیکھ اس بات
کی مانگ کرنا ہے کہ الیکشن کو
سادہ بنا دیا جائے -

وائس چیمبر میں صاحب - میں
یہ نہیں مانتا کہ جلتا ایڈمنسٹریشن
ہے اس میں سب کانگریس وچارے
لوگ ہیں اس میں دوسرے وچاروں
کے بھی لوگ ہیں کچھ کھونسٹ
بھائیوں کے وچارے ہوں گے کچھ
سوتلتر پارٹی کے وچارے ہوں گے کچھ
جن ملکوں بھائیوں کے وچارے والے ہوں
گے اور اس لئے میں یہ نہیں کہتا
کہ صرف کانگریس ہی اپنے لئے
ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرتی ہے
کہونکہ ایڈمنسٹریشن میں کئی طرح
کے لوگ ہیں لیکن یاد رکھئے کہ
ایڈمنسٹریشن کو ٹٹکا جٹا کے سنا
ہونا چاہئے - جیسے ٹٹکا اور جٹا

لاکھوں ورشوں سے یا کروڑوں ورشوں سے
بہتی ہے اور اس کے کنارے پر کبھی
ہوں اُن کبھی آریہ اُن کبھی پتھان
اُن کبھی تغلق اُن کبھی مغل اُن
اور اب وہ اُن ہیں لیکن بہتی
ہے - ناستک ہو آستک ہو وہ سب
کے لئے ہے - تو ایڈمنسٹریشن کو کلک
اور چملا بنائے اور الیکشنوں میں
اگر ایڈمنسٹریشن کا استعمال کریں
کے تو وہ تباہی کا دن ہوگا -
الیکشنوں میں ایڈمنسٹریشن کا
استعمال یا ایمرجسنسی کے دور میں
اس کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا اتنا
ہی زیادہ تباہی کا باعث وہ ہوگا -
تو اگر آپ ایسا کوئی راستہ نکالیں گے
جس سے یہ چیز نہ ہو تو میرا یقین
ہے کہ پھر سے وہی بات پیدا ہو جائے
کی جو کہ گاندھی جی کے وقت میں
تھی کہ ایک آواز دی اور جس کسی
کو کھڑا کر دیا وہ ہو گیا - اس زمانہ
میں اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ کانگریس
کا ہے اس کی جھجکا ہو جاتی تھی اور
یہ کہتے ہیں کہ وہ انگریز کا ہے اس
کی ہار ہو جاتی تھی - انگریز کے
بڑے سے بڑے آدمیوں کی ہار ہو
جاتی تھی - انگریزوں کی کٹلی بھی
نلدا کہیں نہ کروں کہونکہ وہ ہمارے
دیہیوں پر قابض تھے میں نے برس ہا
برس ان کا مقابلہ کیا ان کے ہر قسم
کو اکھاڑنے کی کوشش کی لیکن ایک
بات میں قنکے کی چوٹ پر کہتا

ہوں کہ الیکشن میں انہوں نے
بدنیتی نہیں کی کوئی قبیلہ کھٹ پھوڑ
نہیں چھاپا کوئی ایڈمنسٹریشن کا
استعمال نہیں کیا مگر آج یہ سب
ہو رہا ہے - تو بھارگوا صاحب سے
وائس چیمبر میں صاحب - آپ کے
دوارا اور بھارگوا صاحب کے دوارا میں
ایلی مرکز سے کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ تباہی کا باعث ہوگا - اس لئے
اُنہے ایک ایسا راستہ نکالیں جس
سے کہ پارٹی اپنا مینیسٹر شائع
کردے اور پھر بعد میں کچھ کر لے کو
نہ رہے - میں تو کہوں گا کہ سب
پارٹیوں کا ملتا جلتا مینیسٹر ہو -
وہ دف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نمائندہ
ہے اور آپ اس کو روٹ دو - اتنا کہہ دینے
کے بعد کوئی کہیں نہیں جائے اور
کچھ نہ کرے - ایسا ہے تو اس میں
سب کو آسانی بھی پیدا ہو جائے
لی اور کسی کو ریٹرن بھی نہیں
دینا ہوگا سوائے اس ریٹرن کے کہ میں
کامیاب ہو گیا وہ بھی ریٹرننگ
آفیسر دے دیتا - اگر ایسا ہو تو پھر
کوئی دلت نہیں اُنے گی -

وائس چیمبر میں صاحب - میں
ایک آخری بات کی طرف آپ کی
توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے
کہ میرے ایسا کہنے پر کچھ پارٹیاں
کہیں گی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں
جن میں کہ ہمارے اصولوں میں اور
عواموں کے اصولوں میں مخالفت

[شری عبدالغنی]

ہے جیسا کہ کئی دنوں سے پرائیویٹ
سیکٹر اور پبلک سیکٹر کا جھگڑا چلتا
رہا ہے اور جیسے کہ کمپوزم ہے گاندھی
ایزم ہے اور نہ جانے کتنے ازم ہیں اور
ان کا جھگڑا چلتا ہے مگر یہ سب
ایزم اور ساری پارٹیاں آخر دیسی
واسطوں کے لئے ہیں آخر دیسی
واسطوں کی بھلائی کے لئے ہیں
اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر
آپ وچار کریں اور میری درخواست
پر غور کریں۔ آج آپ یہ نہ کریں
یا کل آپ یہ نہ کریں
لیکن کہی نہ کہی تو کرنا ہی ہو
گا۔ سب پارٹیوں کو مل جل کر کام
کرنا ہی ہے کیونکہ کانگریس کتلی
بھی آگے بڑھ جائے لیکن پھر بھی ہو
سکتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی آجائے۔
سوشلسٹ پارٹی آگے بڑھ جائے یا
کمونسٹ پارٹی آگے بڑھ جائے ہوں
کمونسٹ پارٹی سے تو میں امید
کرتا نہیں وہ تو پیپاس وار کے ساتھ
ہی ختم ہو چکی ہے لیکن کہی
کوئی بھی آسکتا ہے۔ کوئی بھی آگے
مجھے بس سے جھگڑا نہیں ہے۔
میں تو عرض کیا چاہتا ہوں کہ سب
کو مل کر کام کرنا ہے اور اپنے دیسی
کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے
وچاروں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔
چاہے اس معاملہ میں طارق صاحب
یا یا جی جی کچھ بھی کہیں۔ آج

میں اس موقع میں نہیں ہوں اور
مجھے ان سے کوئی جھگڑا کرنا
نہیں ہے۔

श्री अंजुन अरोड़ा: बहुत खुशी की बात है।

شری عبدالغنی: جی ہاں۔

مجھے اور زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے
بھارگوا صاحب سے بھی عرض کرنی
ہے کہ وہ کمپوزم کے ساتھ اس پر
وچار کریں جس سے کہ کسی طرح
ہے تھیموکریسی بھی بچ جائے اور
کسی طرح سے مان بھی قائم رہے۔
جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور دیسی
کی خدمت بھی کسی طرح سے ہو
جائے۔ وائس چیمبر میں صاحب۔
میں بھارگوا صاحب کا شکر گذار ہوں
اور آپ کا بھی شکر گذار ہوں کہ آپ
نے مجھے موقع دیا اور یا جی جی
کا بھی شکر گذار ہوں، طارق صاحب
کا بھی شکر گذار ہوں کہ وہ عین
موقع پر سوئے رہے۔ میں امید کرتا
ہوں کہ ہاؤس کے انٹرپل ممبران
میری اس مودیانہ گزارش پر توجہ
دیں گے۔

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : जब मैं इस
बिल के सूवर पर निगाह करता हूँ तो वह
हिन्दुस्तान के अजीम वर्करों में एक अजीम
वर्कर है। जब मैं उनकी स्मिस्ट को देखता
हूँ तो वह गांधी जी के इस इरशाद "सत्य और
आहिंसा" के पुजारी हैं। सत्य को बापू ने
बड़ा दर्जा दिया। तो वह समझते हैं कि इससे
सत्य का एक अपमान होता है जो यह एक

†[] Hindi transliteration.

[श्री अब्दुल गनी]

लिमिट रखी है, तो काफी मुझे ध्यान से जाना पड़ता है। इस बात में कि उनकी बात में काफी बजान है। जब मैं अपने इन मुअज्जिज साथियों की तकरीरों पर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वे यह समझते हैं कि इसमें सत्य का अपमान होता है। हर एक आदमी को चाहे वह कितना ही बड़ा हो, उसको जो रिटर्न देने पड़ते हैं इलेक्शन कमिशनर को तो उसमें काफी बातों को छुपाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट में जो आज बोटों से आये हैं, उनमें से कितने भाईयों ने गलत बयानी की और गलत बयानों के बाद आया उनको इखलाकी तौर पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस पर जब मैं विचार करता हूँ तो मैं डरता हूँ कि शायद बहुत से, मेजरिटी में, मੈम्बरों को, अगर वे अपने इखलाक को आमने रक्खें तो शायद उनको रिजाइन करना पड़े।

मैं समझता हूँ कि भागव साहब के इस बिल को हाऊस को बड़ी शान के साथ पास करना चाहिए। लेकिन मुझे डर लगता है कि जिस आजादी के लिए, जिस डेमोक्रेसी के लिए, हजारों खूदा के बन्दों ने अपनी जानें कुर्बान कीं, लाखों कुनवों ने अपने आपको बरबाद किया, शायद वे हमें बरबाद करने की तरफ पहला कदम न उठा लें। यह बात यूँ मैं कहता हूँ कि आज तक का इलैक्शनों का तजुर्बा जनाब वाइस चेयरमैन साहब, जो हमारे सामने है उसमें हम यह देखते हैं कि जितने गरीब वर्कर होते हैं उनको तो खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और अगर किसी गरीब वर्कर को कोई पार्टी हिम्मत दिलाए, उत्साह दिलाए, तो वह खड़ा तो हो जाता है, लेकिन जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता वह एक-एक दिन किस तरह बिताता है यह खुदा ही बेहतर जानता है। क्योंकि आज का इलैक्शन बहुत ही मंहगा हो गया है और कोई वर्कर उस शान के साथ जिस शान का वह मुस्तहिक है, जो उसके पहले का गूजरा हुआ जमाना है, उसकी कुर्बानियाँ हैं, उसकी कितनी कीमत कीम को

डालनी चाहिए, या बोटर को डालनी चाहिए यह खासा मुश्किल हो जाता है कि इस तूफान में जो तमाम पार्टियाँ एक दम से बड़े जोर से रुपया बहाती हैं, तो लाखों वर्कर बेवस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं हैं कि वे उनका मुकाबिला कर सकें। फिर यह ध्यान जाता है कि जो यह लिमिट मुकर्रर की गयी थी उस वक्त उसकी जो कीमत थी आज शायद उसका पच्चीस परसेंट भी कीमत नहीं रही क्योंकि हालात ने न सिर्फ कनवेयंस को मंहगा, न सिर्फ प्रिटिंग को मंहगा किया न सिर्फ इस बात को कि वे किस तरह से अपने जलसों का इन्तजाम कर सकें, क्योंकि उनके अखराजात में बहुत ज्यादा इज्जाफा हो गया, बल्कि खाने पीने की चीजें भी मंहगी हो गयीं। तो वह चाहे बोटर हो, चाहे कार्यकर्ता हो, गैर-सरकारी हो, सरकारी हो, उसको बिल्कुल एक मजबूरी की हालत में रहना पड़ता है और बहुत खर्च करना पड़ता है। तो मैं यह समझता हूँ कि इसमें इस लिमिट को जैसा कि उन्होंने कहा है उड़ा देना चाहिए कि कोई रिटर्न भर कर दिया जाए कि इतना खर्चा हुआ। काफी हद तक मेरा उनके साथ खयाल जाता है, लेकिन फिर डरता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छा आदमी या वर्कर जिससे देश का हित हो, जो कि देश की इज्जत अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हो, और इलैक्शन लड़ना चाहे तो कहीं यह पाबन्दी हटने के बाद उसका रास्ता और ज्यादा मुश्किल न हो जाए।

वाइस चेयरमैन साहब, यह एक बड़ा गम्भीर मसला है और हमारे देश का ओ आने वाला जमाना है, उससे इसका बड़ा ताल्लुक है। इसलिए मैं काफी जिम्मेदारी से इस पर विचार करता हूँ। मुझे जो तजुर्बा हुआ, वाइस चेयरमैन साहब, मैंने पिछले दिनों हाऊस में कहा था और मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहता सब के लिए ही कहता हूँ, अपने आपको शामिल करके ही कहता हूँ कि देश सब में बड़ा है। यह हमारे जहन में आए और हम देश को बचाएँ। कई बातों में हम पार्टी को

बड़ा मानते हैं। और इसकी हद से आगे निकल जाते हैं और हर आदमी यह समझता है कि मेरी हस्ती पार्टी से बड़ी है। इसलिए वह अपने आपको और अपनी हस्ती को पार्टी से तरबीह देता है और अपने आपको भूल जाता है। काश मैं इस बात पर अपने इन नेताओं को राजी कर पाता जो कि देश की बागडोर संभाले हुए हैं और आगे भी संभालने की फिक्र में हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा तालीम न फैल जाए जब तक कि लोग पूरी तौर पर सियासी माहौल से वाकिफ न हो जाएं उस वक्त तक हमारे देश में एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। जो अच्छे आदमी इसमें आ सकें उन्हें लिया जाए। जो अच्छे आदमी हैं अगर वो आते हैं तो उन्हें इस बात की फिक्र न हो कि कौन सी पार्टी होगी जो रूल करेगी और किस पार्टी की मर्जी के मुताबिक हमको चलना होगा। काश मैं इस बात पर राजी कर पाता अपने नेताओं को जो हमारे पूज्य बापू की बातों को जूब गए हैं जो कि महात्मा गांधी चाहते थे।

मुझे बड़ी खुशी है कि सन्सना साहब ने अपनी तकरीर में यह कहा कि किसी भी पार्टी को देश में महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी कामयाबी के लिए और दूसरों को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन मैं इस आगस्ट हाऊस में खड़ा हूँ और मैं इमान्दारी से कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के दिमाग में यह बात थी कि इस मुल्क में हरिजन बेटी प्राइम मिनिस्टर बने और राष्ट्रपति बने, तो उनके दिमाग में इस तरह की बात थी। अगर हमारे मुल्क के नेता ऐसा रंग पैदा कर दें और लोग ये न देख पाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन नीची जात है और कौन ऊंची जात का है तो इससे हम एक नयी फ़िजा मुल्क में पैदा कर सकते हैं। उनके दिमाग में जो ये सबसे बड़ी बात थी कि एक हरिजन नईकी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बने, तो उनकी मन्शा यह थी कि

हमारे जो इलैक्शन हैं, हमारे जो चुनाव हैं, वह हर तरह से बुराई से पाक हों, हर तरह की मुश्किलात आसान हों, और हर एक के लिए यह चान्स हो कि वह अपने देश की खिदमत जिस तरह चाहे कर सके। और इस चीज का उसे पूरा मौका दिया जाए।

मैं इस तरह की स्पिरिट नहीं ला सकता हूँ और न मैं किसी को राजी कर सकता हूँ, लेकिन देश सबसे बड़ा है और बाकी चीजें उसके नीचे हैं। हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े आदमी हैं वे सब देश के लिए हैं, देश उनके लिए नहीं है। देश सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैंने पिछले दिनों एक बार कहा था—

इक तजे कुल के लिए कुल तजे पुरहित,
पुर तजे हित देश के देश तजे जग हित।

अगर एक खानदान को बचाना है तो एक आदमी को कुर्बान कर दो। अगर एक गांव को बचाना है तो खानदान को कुर्बान कर दो। अगर देश को बचना है तो गांव को कुर्बान कर दो। मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर देश वासी किसी को अपनी आत्मा का खून करने को कहता है तो वह देश को भी छोड़ दे। मेरा कहना यह है कि मैं भार्गव साहब से मुत्ताफ़िरक नहीं हूँ और मैं इस बिज की मुखाजिफ़्त करना चाहता हूँ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ, बाइस चेयरमैन साहब, कि इससे बुराई का हल नहीं निकलता। वो लोग जो एसम्बली और पार्टी के मँम्बर बनते हैं उनको यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि जितनी रकम इलैक्शन में लड़ने के लिए कानूनी तौर पर मुकर्रर है उससे कहीं ज्यादा उन्हें खर्च करना पड़ता है, और इस वजह से उनको जब स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ता है तो वे झूठा स्टेटमेंट दाखिल करते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस चीज को हटा दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि यह गलत रास्ता है। रास्ते दो ही हो सकते हैं या तो आप यह तय कर लीजिये कि सिर्फ़ अमीरों के बिना

एसम्बली हो, पार्लियामेंट हो, और उसमें वोही बोग जाएं जो कि हजारों और लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, और जो गरीब आदमी है, चाहे कितना ही काबिल क्यों न हो, चाहे कितनी ही लियाकत क्यों न रखता हो, उसके लिए कोई चान्स नहीं है। आप भी यह मानेंगे कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसको भी इन्डस्ट्रियलिस्ट का सहारा लेना पड़ता है, सरमायेदारों का सहारा लेना पड़ता है और बड़े-बड़े बिजनेसमैनो का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं गलत न कहूं तो कई जगह तो वह अपने अधिकारियों का नाजायज फायदा उठाती है।

वाइस चेयरमैन साहब, मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लाखों रुपया जो पिछले इलेक्शन में इकट्ठा किया था अपने पास अभी तक जमा कर रखा था। वे कहते हैं कि यह रुपया मुझे इलेक्शन फंड में दिया गया था और मेरे घर में पड़ा था; पुड़ियों में पड़ा था, और कागजों के बंडलों में पड़ा था और अब मैं दो बरस के बाद उसको वापिस करने जा रहा हूं। वे अब दिलेर बन गए कि लोगों का रुपया दो बरस बाद वापिस करने जा रहे हैं। एसम्बली सीट के लिए तो सात हजार रुपया कानूनी सीट पर एक आदमी खर्च कर सकता है तो उन्होंने इतना रुपया क्यों इकट्ठा किया? वे कहते हैं कि पार्टी फंड के लिए यह रुपया दिया गया, तो यह रुपया पार्टी को क्यों नहीं दिया गया? अगर वे कहते हैं कि सब पार्टियों के लिए दिया गया तो सब पार्टियों को क्यों नहीं दिया गया? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी सूरत में एक अजीब रंग हमारे सामने आ जाता है जो खराबी का वाइस होगा।

आखिर हम का क्या हल निकाला जाए। मैं अप्पेस करता हूं कि मैं अन्वर साहब की अजीमुलशान तकरीर को नहीं पुन पाया। लेकिन मैं समझता हूं वाइस चेयरमैन साहब, कि भागव साहब जो हमेशा बुलन्द ख्याल रखते हैं जिनकी नियत बुलन्द है, जिनकी

इज्जत मैं हमेशा करना था और हमेशा करता रहूंगा, मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि वे कोई ऐसा रंग पैदा करें जिससे डिमांडेरी फायम रहे। छोटे लोग भी आगे आ सकें। छोटे लोग भी आजादी से राय दे सकें। अगर इस तरह का कोई साधन हो सकता है तो उन्हें लाना चाहिये बजाय इसके कि ये एमेंडमेंट लाते। उन्हें तो इस तरह का अमेंडमेंट लाना चाहिये था कि आल इंडिया रेडियो से सब पार्टियां अपना मैनीफेस्टो तैयार करके, अपनी खूबियां बता कर के, उस को ब्रडकास्ट करें कि इस तरह से कि हमारे वक्ता हैं और इस तरह के उम्मीदवारों को वोट दें। हमें आल इंडिया बेसिस पर सब पार्टियों को एक इस तरह का प्रोग्राम बना लेना चाहिये जिससे वे मुल्क के लोगों के सामने अपनी पार्टी का प्रोग्राम रख सकें। अगर हम एमरजेंसी के जमाने में एक जगह इकट्ठा हो सकें तो हम फिर इस बात का ख्याल क्यों नहीं करते कि जो आने वाले इलेक्शन हैं उनमें सिर्फ पार्टी का पैगाम हो और वोटों का खूली छूट दी जाय कि वे इन आदमियों पर जो लोग आते हैं उन्हें ही वोट दें? अगर सबको यह ध्यान में रख हो तो शायद ही कोई गांव ऐसा होगा, कोई देहात ऐसा होगा जहां कि आल इंडिया रेडियो की आवाज न पहुंचती हो। तो इसके साथ ही साथ सब पार्टियों के नेताओं की तरफ से हिन्दी में, रीजनल लैंग्वेज में, और अंग्रेजी में यह निकाल दिया जा कि इन यह चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आप वोट दें। अगर हम इस तरह के मूवमेंट पोस्ट आफिसेज के जरिये लोगों के घर पहुंचा तो न हमें पब्लिक मीटिंग करनी पड़ेगी और न इन मीटिंगों में गरमागर्मी आएगी, न हम गन्दे इश्तहार निकालेंगे न हम किसी दूसरे पर हमला करेंगे, और सब लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि हमने फनों को चुन लिया है, उसमें ये अच्छाईयां हैं, उसको ही वोट देना चाहिये, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो। जिस दिन वोट पड़ेंगे उससे एक महीने पहले न कोई जलसा हो, न कोई

[श्री अब्दुल गनी]

इश्तहार बाजी हो, न कोई अफसर किसी को कोई परमिट दे, न किसी को लाइसेंस दे और न किसी को इंसेंशिल साटिफिकेट दिया जाय, और न ही किसी को कर्जा दिया जाए। अगर ऐसा रास्ता निकाल दिया जाय तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि न हमें पच्चीस हजार खर्च करने की जरूरत पड़ेगी और न सात हजार खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं क्यों कहता हूँ। आखिर हम सब दिलो जानसे—कोई भी पार्टी हो, मेरा यकीन है कि डेमोक्रेसी में सबका ईमान है—चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे। तो कोई इसका साधन कीजिये, बरना कोई बुराई एक है? आप जानते हैं कि सिर्फ रुपए की ही बुराई नहीं है, रुपय की भी बुराई है—अपनी आत्मा का खून करना पड़ता है। जब कोई रिटर्न देता है, उस को पता होता है कि मैंने पच्चीस हजार की जगह सान लाख रुपया खर्च किया है।

बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं है। जो मेरे पहले श्री आनरेबुल मैम्बर बोले उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को छोड़ दो, बाकी तो सब थोड़ा खर्च करके होते हैं। मैं जानता हूँ कि एक जमाने में जब कांग्रेस किसी के साथ पर लिख देती थी कि यह आप का खि गुजर है और हम अपील करते थे कि लोग इस को बोट दें तो मुझे याद है कि बड़े बड़े राजा, बड़े-बड़े अमीर लोग, बड़े-बड़े बैरिस्टर लोग, बड़े जमींदार लोग एक गरीब से गरीब के मुकाबले में हार जाते थे। लेकिन आज मुझे यह डर है कि और हालात का तकाजा यह है कि आप खफा न हो जाएँ अगर पं० जवाहर लाल नेहरू भी आज रिजाइन कर के मुकाबिला करें तो शायद वे भी हार जाएँ। दुनिया के हालात बदलते रहते हैं और आप वह थिंकिंग अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिये। अंग्रेजों के मुकाबले में यकीनन कांग्रेस मुल्क की एक वाहिद नुमाइंदा जमात थी और उसमें सब पार्टियां शामिल थीं। चाहे वह सोशलिस्ट हो चाहे प्रजा सोशलिस्ट हो, चाहे स्वतन्त्र हो, चाहे

जनसंघ के भाई हों, चाहे अकाली हों, चाहे कम्युनिस्ट हों—वे सब के सब कांग्रेस के झंडे के तले थीं। यह बात भूलग है कि जब हमने आखरी जंग लड़ी तो उस वक्त कम्युनिस्ट भाइयों का दिमाग पीपुल्स वार की तरफ चला गया था। लेकिन यह सच है कि उस में सब के सब शामिल थे और कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी। कांग्रेस मुल्क की आजादी के लिये थी, मुल्क कांग्रेस के लिए नहीं था। अगर यह बात रूलिंग पार्टी के दिमाग में आ जाए जोकि इस वक्त अकमरियल में है तो उस को यह सोचना चाहिये कि पता नहीं कि हम पांच बरस जीएं, दस बरस जियें, लेकिन इस देश को सदा रहना है और उस वक्त तक रहना है जब तक दुनिया का नाश न हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम को सोचना है कि इल्लेक्शन का ढंग क्या हो और इस को आप जितना साधारण कर सकें उतना अच्छा है।

भार्गव साहब जो बिल लाये हैं मुझे पता नहीं इन्क्वेशन कमिश्नर की उम्र पर क्या राय भाई है। लेकिन मेरा यकीन है कि अगर यह ठीक है तो उस को सब पार्टियों के सामने लाना चाहिये। सवाल यह भी है कि यह उठ रही स्वतन्त्र पार्टी जो दिनों में आसा बढ़ गयी वह क्यों बढ़ गयी। कोई कह सकता है कि वह दौलत के जोर पर बढ़ गयी और वे कह सकते हैं कि हम अपनी आइडियालाजी के जोर पर बढ़ गये।

वाइस चेयरमेन साहब, इस वक्त कांग्रेस जो सब से बड़ा अपना ध्येय मानती है वह सोशलिज्म का ध्येय है। वे चाहते हैं कि ऐसा रंग जमाया जाये जिस में काफी एकता आ जाये और उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब और अमीर का फर्क जो है कम हो जाए। आज कई जगह वो फर्क सौ गुना का है, कई जगह तीस गुना का है, और वे चाहते हैं कि वह बिल्कुल मामूली रह जाये। अमरीका जैसे मुल्क में भी एक बड़े अफसर की तनख्वाह में और एक छोटे सिपाही की तनख्वाह में

दस गुना से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तकरीबन दस गुना पड़ता है। अगर कांग्रेस दिल से कहती है कि हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो आप फिर इस बात की तरफ आइए कि वह खर्चा जो इलैक्शन का है यह कतई खत्म न हो, लेकिन यह नाम मात्र रह जाए, और नाम मात्र भी यूँ रह जाए कि जाती तौर पर कोई कैंडिडेट बिल्कुल अपना खर्चा न करे। उसकी कुर्बानी या उसकी काबलियत या उसकी खिदमत या उसकी हिम्मत इन चारों बातों में जोग ऐहसास करें कि इस के जाने से हमारे देश का भला होगा। अगर यह बात हो जाए तो मैं भार्गव साहब को जिन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है मुबारिकबाद दूंगा। ऐसी सूरत में देश ऊंचा उठेगा, देश में एक नया उभार आएगा, देश में यह ख्याल आएगा कि देश हमारा है, और चाईना क्यों न हो, पाकिस्तान क्यों न हो, रशिया क्यों न हो, अमरीका क्यों न हो हम सब का मुकाबिला कर पायेंगे। क्योंकि उस वक्त सब के सामने सब से पहली कसम यह होगी, यहां आ कर नहीं खड़े होने से पहले उम्मीदवार जो बना है उसके सामने, कि हम को अपनी जात से, अपने खानदान से, अपनी पार्टी से देश ज्यादा प्यारा है। जब इस बात को हम सामने रखेंगे और अखराजात की बिल्कुल मुमानियत कर देंगे तो मेरा यकीन है कि सिर्फ पार्टियां रह जायेंगी जो प्रचार करेंगी।

यह मैं मानता हूँ कि बहुत कठिनाइयाँ हैं। जैसेकि आप यहां वाइस चेयरमैन साहब हुकम देते हैं कि ऐज एक तरफ हरे बल्ब पर उंगली रखें और जो नोज वाले हैं वो लाल बल्ब पर उंगली रखें और जो न्यटरल हैं वो फ्लां बल्ब पर उंगली रखें, यह मैं मानता हूँ कि आज यह ऐसा मुमकिन नहीं कि गांव में हम यह इन्तजाम कर सकें और सारे देश में पांच मिनट में ही सब तय हो जाये, और किसी पर किसी तरह का बोझ भी न पड़े। लेकिन अगर मुझे मुआफ किया जाये तो मैं यह कहूंगा कि मैंने यह देखा कि पिछले इलैक्शन

में डबल बैलेट पेपर छपे। उन के छापने की जिम्मेदारी किस पर है? जिस तरह आज कोई खाली नोट शायी करे तो उस की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर नहीं है, फाइनेन्स मिनिस्टर पर नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर पर नहीं है बल्कि वह जिम्मेदारी है उस पर कि जो ऐसा करता है। हमारे पंजाब में भी जो डबल बैलेट पेपर छपे, मैं उसे किसी तरह से भी जिम्मेदारी इलैक्शन कमिश्नर या उन के स्टाफ पर नहीं डालता। लेकिन यह क्यों होता है? यह बात इसलिये होती है कि एक पार्टी कसम खाए हुए होती है, चाहे वह अपोजीशन पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कि हमें दूसरे को गिराना है और ताकत में आना है। उस वक्त न सिर्फ पच्चीस हजार के बजाय दो-दो लाख रुपया खर्चा हो जाता है बल्कि वे ऐसी बातें भी करते हैं जो आने वाली मस्लों के लिये शर्म का बाइस बनेंगी। इसलिये आप इलैक्शन का सादा कीजिये। और ऐसी कोशिश कीजिये कि जब राय ली जाये वो इस ढंग से ली जाये कि एक ही वक्त में हर गांव में बजाय इतना बड़ा स्टाफ भेजने के या इतने बड़े जोये जाते हैं आप के अफसर और उन का बड़ा अमला और उस के इन्तजाम के लिए पुलिस न जाने क्या क्या कुछ होता है। जितने भी उम्मीदवार हों एक हो, दो हों, तीन हों, सरकार ऐसा इन्तजाम करे कि वे अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर इकट्ठा हो जायें, और उनका एक ही वक्त में जो टाइम मुकर्रर हो, जो भी टाइम आप मुकर्रर करें, उस में फोटोग्राफ हो जाये, और वह फोटोग्राफ जो हो वह सरकार के पास पहुंच जाए। सरकार से मेरी मुराद रिटर्निंग आफिसर से है। तो उस में ये जो वोटों का संश्लेषण है—मैं खड़े हो कर के कहूं या कोई कुछ खड़ा हो कर के कहे—उस में भी काफी हद तक आसानी हो जाती है और भार्गव साहब जो चाहते हैं कि सच्चाई का इजहार हो वह भी हो जायगा कि किस कैंडिडेट के पास कितने लोग हैं। तो इस तरह उन को कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा और इस एमरजेंसी के

[श्री अब्दुल गनी]

जमाने में सरकार का भी खूब कम हो जायेगा, और सरकार जो एमरजेंसी में इन्ट्रेशन चाहती है ज इमोशनल हो, नोशनल हो किसी तरह का हो, उस को भी चक्का नहीं लगेगा ।

इसके बाद हो सकता है कि हमारे बेतागण इस बात पर भी आ जाएं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा देश अशोक जी के जमाने में था या अकबर के जमाने में था या चन्द्रगुप्त के जमाने में था उसी तरह से फिर देश को खुशहाल बनाया जाये, और जैसे पहले तक्षशिला और पाटलीपुत्र की यनिक्सिटियों की तरफ सारी दुनिया आती थी उसी तरह फिर सब हिन्दुस्तान की तरफ निगाहें करने लयें, और हिन्दुस्तान सिवाए तामीर के तखरीब का नाम न जानता हो । और तब नफरत जो पार्टियों की तरफ होती है उस को कम से कम किया जाये । जो देहात में, झगड़े होते हैं उन को कम से कम किया जाये । जो सच्चाई चाहते हैं, मार्गव साहब, वो सच्चाई भी जाहिर हो सके । उस के लिए और भी कई बातें और कई स्कीमें हो सकती हैं । जिस से सच्चाई ज्यादा से ज्यादा उभरे और इसलिये उभरे कि हम अपने देश की ताकत में इजाफा करें ।

जिन नेताओं के साथ मेरा जिन्दगी का वास्ता रहा और मैंने बरसों बरस उनके साथ काटे आज मैं उनसे कहना चाहता हूं क्योंकि उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और उनके बाद अपोजीशन के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आखिर ताकत किस लिए लेते हैं । ताकत इसलिए लेना चाहते हैं कि हम देश को सर्व करें, देश की हम खिदमत करें । चन्द गन्दी मछलियां जो होती हैं वो बेशक सारे तालाब को गन्दा कर देती हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, सब की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है । मैं यह बड़े फ़ख़र से कह सकता कि अक्सरियत जो होती है मेम्बरों की वह ईमानदारी से यह चाहती है कि देश का भला हो, देश का मान रहे । लेकिन आज वाइस चेयरमैन साहब, हमारे

प्राइम मिनिस्टर जिनका दर्जा दुनिया में बहुत ही बलुन्द था, ख़दा करे अभी भी बलुन्द रहे

श्री ए० एम० तारिक : है अभी ।

श्री शीलभद्र याजी : हो क्या, अभी भी है ।

श्री अब्दुल गनी : सुनने से पहले ही आप बेकरार हो गए, तारिक भाई और याजी जी । मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था ।

श्री ए० एम० तारिक : हम जानते हैं कि आप क्या कहेंगे ।

श्री अब्दुल गनी : उस वक्त जब मैंने कहा था और जब मैंने चैलेंज किया था कि पंडित जी रिजाइन करें उस वक्त आपको चैलेंज कुबूल करना था, लेकिन उस वक्त आप लोग सोये रहे । मैं जानता हूं कि आज भी उन का बड़ा मान है । अब आप खुल हो गए । ऐसे अजीम आदमी को भी बाज़-ओक्रात अपनी पार्टी को ताकत में रखने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं और अपने मन के खिलाफ़, अपनी राय के खिलाफ़ व मजबूर हो जाते हैं कि पार्टी के लिए ऐसी बातें करें जिसको लोग बिल्कुल न मानें ।

श्री शीलभद्र याजी : ग़लत बान है ।

श्री अब्दुल गनी : आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जो बात मेरी है वह मैं ही कहूंगा :—

निकल जाती है सच्ची बात

जिस के मुँह से मस्ती में,

फ़कीद्रे मसलहत बीं से वो

रिदे बादा ख़ार अच्छा ।

मैं ऐलान से कह सकता हूं कि मैं आज भी पंडित नेहरू का ज्यादा दोस्त हूं बामुकाबिला उनके जो उनकी बातों को सेबोटैज करते हैं और इस तरीके पर करते हैं कि जिससे दुनिया उनका मजाक करे, जिससे महज्जब दुनिया हंसे और उनकी चर्चा करे ।

इसलिए वाइस चेयरमैन साहब, मैं यह कह रहा था कि अगर हमारी नीयत यह है कि इलेक्शनों में जो भी कैंडिडेट हों उनकी बिसमिल्ला ही गलत न हो कि वे अपना रिटर्न ही गलत दें, बल्कि उनकी बिसमिल्ला ठीक हो, तो उसके बारे में हमें कुछ करना होगा। क्योंकि जब उनकी बिगनिंग ठीक होगी तो उनका एंड भी शानदार ही होगा। तो इसलिए मैं आपके द्वारा वाइस चेयरमैन साहब, सरकार से कहता हूँ कि वह ऐसे साधन अख्तियार करे जिससे कि कम से कम खर्च पर गरीब से गरीब उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ सके और मुकाबिले में खड़ा हो सके। उसमें कोई दिक्कत उसे न आए। और ऐसी सूरत न हो कि कोई स्वतंत्र पार्टी का राजा हो या कोई कांग्रेस पार्टी का नवाब हो या कोई जनसंघ का राजा हो वह गरीब आदमी को रुपये के जोर से दबा दे। तो अगर आप ऐसा संशोधन करें कि जिसमें कोई गरीब से गरीब उम्मीदवार भी आसानी से खड़ा हो सके तो बहुत बेहतर होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इलेक्शनों में एक तरफ जीप की कतारें होती हैं जैसाकि चाइना को हटाने के लिए एक फौज जा रही हो और दूसरी तरफ गरीब के पास एक छोटा सा छकड़ा भी नहीं होता। इलेक्शन में आपके सामने ऐसी बातें आई हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जो अनहोनी बात हो। ऐसा हुआ है, इसलिए कहता हूँ। तो भार्गव साहब, बजाये इसके कि ये एमेंडमेंट लाएं उनके लिए यह बेहतर है कि वो अपना खुलूस, अपनी काबलियत, अपनी विजडम इस बात पर लगाएं कि इस हाउस में भी और जो हमारी लोक सभा है उसमें भी इस बारे में उनकी आवाज पहुंचे कि सच्चाई इस बात का मुताबिलवा करती है, देश इस बात की मांग करता है, कि इलेक्शन को सादा से सादा बनाया जाये।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं यह नहीं मानता कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सब कांग्रेस विचार के लोग हैं जिनमें जिनके

विचारों के भी लोग हैं, कुछ कम्युनिस्ट भाईयों के विचार के होंगे, कुछ स्वतंत्र पार्टी के विचार के होंगे, कुछ जनसंघी भाईयों के विचार के होंगे। और इसलिए मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेसी ही अपने लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह के लोग हैं। लेकिन यदि रखिए एडमिनिस्ट्रेशन को गंगा-जमना के समान होना चाहिये। जैसे गंगा और जमना लाखों वर्षों से या करोड़ों वर्षों से बहती हैं और उसके किनारे पर कभी ठुण आए, कभी आये आए, कभी पठान आए, कभी तुगलक आए, कभी मुगल आए और अब वे आए हैं लेकिन वह बहती है। वास्तिक हो वास्तिक हो वह सब के लिए है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को गंगा और जमना बनाइए और इलेक्शनों में अगर एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वह तबाही का कारण होगा। इलेक्शनों में एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल या एमरजसी के दौर में इसका इस्तेमाल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तबाही का बाइस वो होगा। तो अगर आप ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि यह चीज न हो तो मेरा यकीन है कि फिर से वही बात पैदा हो जायेगी जोकि गांधी जी के वक्त में थी कि एक आवाज दी, और जिस किसी को खड़ा कर दिया वह हो गया। उस जमाने में इतना ही कहने से कि यह कांग्रेस का है उसकी जीत हो जाती थी और यह कहने से कि वो अंग्रेज का है उसकी हार हो जाती थी। अंग्रेज के बड़े से बड़े आदमियों की हार हो जाती थी। मैं अंग्रेजों की कितनी भी निन्दा क्यों न करूं क्योंकि वो हमारे देश पर काबिज थे, मैंने बरसा बरस उनका मुकाबला किया उनके हर कदम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन एक बात मैं उनके की चोट पर कहता हूँ कि इलेक्शनों में उन्होंने बदनीयती नहीं की, कोई इन्फ्लिकेट पेपर नहीं छापा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया। मगर आज वह सब को गदा है। तो भार्गव साहब से,

[श्री अब्दुल गनी]

वाइस चेयरमैन साहब, आपके द्वारा और भागव साहब के द्वारा मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह तबाही का बाइस होगा। इसलिए आइए एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि पार्टी अपना मैनिफेस्टो शायद कर दे और फिर बाद में कुछ करने को न रहे। मैं तो कहूँगा कि यह सब पार्टियों का मिश्रता जुलता मैनिफेस्टो हो। वो सिर्फ यह कह दे कि यह हमारा नुमाइन्दा है और आप इसको वोट दो। इतना कह देने के बाद कोई कहीं न जाए और कुछ न करे। ऐसा हो तो उसमें सबको आसानी भी पैदा हो जायेगी और किसी को रिटर्न भी नहीं देना होगा, सिवाय इस रिटर्न के कि मैं कामयाब हो गया और वो भी रिटर्निंग आफिसर दे देगा। अगर ऐसा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं एक आखिरी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और वह ये है कि मेरे ऐसा कहने पर कुछ पार्टियाँ कहेंगी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कि हमारे असूलों में और दूसरों के असूलों में मुद्दालफत है, जैसा कि कई दिनों से प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर का झगड़ा चलता रहा है और जैसे कि कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, गांधीइज्म है और न जाने कितने इज्म हैं और उनका झगड़ा चलता है। अगर वे सब इज्म और सारी पार्टियाँ आखिर देशवासियों के लिये है, आखिर देशवासियों की भलाई के लिये है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर आप विचार करें और मेरी दरखास्त पर गौर करें। आज आप यह न करें या कल आप यह न करें लेकिन कभी न कभी तो करना ही होगा। सब पार्टियों को मिश्र-जुलकर काम करना ही है क्योंकि कांग्रेस कितनी भी आगे बढ़ जाये, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी

आ जाए स्वतन्त्र पार्टी आगे बढ़ जाए या कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ जाए। यूँ कम्युनिस्ट पार्टी से तो मैं उम्मीद करता नहीं, वो तो पीपल्स वार के साथ ही खत्म हो चुकी है लेकिन कभी कोई भी आ सकता है। कोई भी आए मुझे उससे झगड़ा नहीं है। मैं तो यह अर्ज किया चाहता हूँ कि सबको मिलकर काम करना है और अपने देश की भलाई को सामने रखते हुए अपने विचारों को लोगों के सामने रखना है। चाहे इस मामले में तारिक साहब या याजी साहब जी कुछ भी कहें। आज मैं इस मूड में नहीं हूँ और मुझे उनसे कोई झगड़ा करना नहीं है।

श्री अर्जुन अरोड़ा : बहुत खुशी की बात है।

श्री अब्दुल गनी : जी हाँ। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। भागव साहब से यही अर्ज करनी है कि वे गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें जिससे कि किसी तरह से डमोक्रैसी भी बच जाए और किसी तरह से मान भी कायम रहे। झूठ भी न बोलना पड़े और देश की खदमत भी किसी तरह से हो जाये। वाइस चेयरमैन साहब, मैं भागव साहब का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और याजी जी का भी शुक्रगुजार हूँ, तारिक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वे ऐन मौके पर सोये रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाऊस के आनरेबल मेम्बरान मेरी इस मोअद्दबाना मुजादरिश पर तवज्जो देंगे।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The Home Minister will now make a statement.